लखनऊ

गुरुवार, 4 जून, 2026

वर्ष : 11 । अंक: 278

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

घर के अंदर जी भर के रो लो, पर दरवाजा हंस कर ही खोलो।

TODAY WEATHER

DAY 42° Hi

NIGHT 29° Low

संक्षेप

कम बारिश और ज्यादा तपिश... अल-नीनो बिगाड़ेगा भारत में मानसून का खेल, WMO की चेतावनी

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रशांत महासागर में गर्म पानी के चलते अल-नीनो तेजी से बन रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने मंगलवार को इसपर जारी अपडेट में चेतावनी दी है। इससे वैश्विक तापमान और बारिश के पैटर्न पर गहरा असर पड़ेगा साथ ही आने वाले महीनों में मौसम संबंधी घटनाएं बढ़ने का खतरा है। WMO के अनुसार जून से अगस्त के बीच अल-नीनो बनने की 80 प्रतिशत तक संभावना है। यह लगभग तय माना जा रहा है कि भारत का मॉनसून कमजोर रहेगा। जून का महीना सामान्य से अधिक गर्म रहेगा, जैसा कि भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पहले ही अनुमान लगाया था। हालांकि अल-नीनो की तेजी और समय को लेकर अभी अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन अधिकांश मॉडल इसे कम से कम मध्यम श्रेणी का बता रहे हैं। WMO ने कहा कि एल-नीनो के नवंबर तक जारी रहने की 90 प्रतिशत की संभावना है। इसका मतलब है कि पूरे दक्षिण-पश्चिम मॉनसून सीजन पर इसका असर रहेगा, जो खरीफ फसलों की बुवाई का समय है। WMO महासचिव सेलेस्टे साउलो ने कहा, '2023-24 का हालिया एल-नीनो रिकॉर्ड पर दर्ज पांच सबसे मजबूत एल-नीनो में से एक था। इसने 2024 में देखे गए रिकॉर्ड तोड़ वैश्विक तापमान में भूमिका निभाई थी।' संगठन ने सरकारों को सूखा, भारी बारिश, लू और समुद्री-स्थलीय दोनों जगहों पर गर्मी के बढ़ते खतरे के लिए तैयार रहने की सलाह दी है।

नीट यूजी पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्रालय ने शुरू की कार्रवाई

नई दिल्ली, एजेंसी। नीट-यूजी प्रवेश परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर सख्त प्रशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही मामले की गहन जांच जारी है। सूत्रों के अनुसार, शिक्षा मंत्रालय ने एक निजी कंपनी कोएम्ट को विवादास्पद परिचालन अनुबंध दिए जाने के संबंध में औपचारिक रूप से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि जांचकर्ता कंपनी की तकनीकी योग्यता और पिछले प्रदर्शन के रिकॉर्ड की बारीकी से जांच कर रहे हैं, ताकि यह समझा जा सके कि परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उसे कैसे सौंपी गईं। मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार कथित डेटा उल्लंघन और पेपर लीक की घटना को अत्यंत गंभीरता से ले रही है। मंत्रालय ने कड़ी चेतावनी जारी की है कि लापरवाही या मिलीभगत के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी या बाहरी प्रतिनिधि के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार कथित सुरक्षा खामियों की पूरी सीमा का पता लगाने के लिए साइबर सुरक्षा एजेंसियों और परीक्षा बोर्ड के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय कर रही है। यह आंतरिक जांच प्रशासनिक तंत्र को साफ करने के तत्काल प्रयास का संकेत देती है। परीक्षा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने हाल ही में प्राथमिक जांच प्रमुख केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दी है। इसके अलावा, डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार करने, केंद्रों पर सख्त बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य करने और भविष्य में लीक को रोकने के लिए पेपर ट्रांसमिशन के लिए उन्नत एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल लागू करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

दिल्ली में 6 मंजिला होटल में आग, 21 की मौत:मरने वालों में ज्यादातर विदेशी, 40 को बचाया, जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूदे लोग

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण होटल अग्निकांड ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है, जबकि दर्जनों लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई लोगों को अपनी जान बचाने के लिए होटल की ऊपरी मंजिलों से छलांग तक लगानी पड़ी। फायर ब्रिगेड और राहत टीमों ने समय रहते कार्रवाई करते हुए करीब 37 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि कई लोग धुएं और आग की चपेट में आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक होटल के अंदर अफरा-तफरी का माहौल था और लोग किसी भी तरह बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। अब इस हादसे के बाद कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि जिस होटल में आग लगी, वहां केवल छह कमरों की अनुमति थी, लेकिन इमारत में कथित तौर पर 25 कमरे संचालित किए जा रहे थे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इतने कमरे बनाए गए थे तो फायर सेफ्टी के नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया? बताया जा रहा है कि इमारत में बाहर निकलने के लिए केवल एक ही रास्ता था और अलग से फायर एग्जिट मौजूद नहीं था। घटनास्थल के आसपास मौजूद अन्य इमारतों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों और रिपोर्टरों ने इलाके की कई ऐसी बहुमंजिला इमारतों की ओर इशारा किया है, जहां सुरक्षा मानकों को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं। हादसे के बाद प्रशासन अब ऐसे भवनों की जांच की तैयारी में है। बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय ने भी अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि अगर जांच में किसी तरह की लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि ऐसे सभी गेस्ट हाउस, होटल और बीएनबी की जांच की जाएगी, जहां सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल हैं।

हालात पर बारीकी से नजर: CM रेखा

मुख्यमंत्री रेखा ने आगे कहा, "आग लगने की घटना की जानकारी मिलते ही, दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, DDMA, CATS एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों की टीमों को तुरंत सक्रिय कर दिया गया, जिन्होंने बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिए। त्वरित कार्रवाई की मदद से वहां फंसे कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने और बचाने में सफलता मिली।" हालात को लेकर मुख्यमंत्री रेखा ने कहा, "दिल्ली सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए है। प्रभावित परिवारों को सभी जरूरी मेडिकल मदद और सहयोग प्रदान किया जा रहा है। दुख की इस घड़ी में, दिल्ली सरकार प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। हम इस त्रासदी से प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

अग्निकांड पर दुख जताया। उन्होंने कहा, "मालवीय नगर में आग लगने की घटना से मन अत्यंत व्यथित है। स्थानीय प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुटा हुआ है। इस हृदय विदारक घटना में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। ईश्वर शोकाकुल परिवारों को यह दु:ख सहने की शक्ति प्रदान करें। घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

PM मोदी ने मालवीय नगर अग्निकांड पर जताया दुख, पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान

दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक रेस्टोरेंट में आज बुधवार सुबह भीषण आग लगने से कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। हादसे में बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। राहत और बचाव अभियान के जरिए 30 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। मालवीय नगर अग्निकांड पर पीएम नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया और हादसे में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना जताई। साथ ही हादसों के शिकार लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया। अमित शाह और प्रियंका गांधी ने भी हादसे पर दुख जताया। मालवीय नगर में लगी भीषण आग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया X पर अपने पोस्ट में कहा, "मालवीय नगर में आग लगने की घटना में लोगों की जान जाना बेहद दुखद है। हादसे में जिन लोगों ने अपने-अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी गहरी संवेदनाएं हैं। साथ ही मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने में लगा हुआ है।" PM मोदी ने ऐलान किया कि हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों PMNRF के तहत हर मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। साथ ही घायलों को 50,000 रुपये की मदद दिए जाएंगे।"

मालवीय नगर के एक होटल में आग लगने के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मौत और करीब 3 दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने का समाचार अत्यंत हृदयविदारक है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। शोकसंतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।"
उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के साथियों से मेरी अपील है कि कृपया प्रभावित लोगों की यथासंभव मदद करें।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा

25 प्रस्ताव पास, 17 नगर निगमों चलेंगी नई ई-बसें, जेवर एयरपोर्ट भी होगा कनेक्ट

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। यूपी में बुधवार को कैबिनेट में कुल 25 प्रस्ताव रखे गए। इसमें 24 प्रस्ताव पास हुए। प्रदेश के 17 नगर निगमों और नोएडा में 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएंगी। इन बसों का संचालन नगर क्षेत्रों के साथ-साथ उनकी परिधि में आने वाले क्षेत्रों तक किया जाएगा, जिससे आम लोगों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिल सकेगी।

योजना के तहत 9 मीटर लंबाई की 725 और 12 मीटर लंबाई की 1000 ई-बसें चलाई जाएंगी। वर्तमान में 733 ई-बसें पहले से संचालित हैं। नई व्यवस्था में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर एयरपोर्ट) को भी सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।

परियोजना के संचालन के लिए विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) का गठन किया जा चुका है और ऑपरेटिंग कंपनियों का चयन भी हो गया है। योजना पर कुल 1852 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें सरकार पर 653 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा, जबकि शेष निवेश ऑपरेटर करेंगे।

सरकार बस डिपो और अन्य आवश्यक आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराएगी। साथ ही किराये और निविदा (बिडिंग) के बीच होने वाले अंतर की भरपाई भी सरकार करेगी। सरकार का मानना है कि इस योजना से शहरी परिवहन को नई गति मिलेगी और प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी।

4000 MoU, 85 देशों की होगी भागीदारी...यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का चौथा संस्करण जल्द

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) 2026 का आयोजन किया जा रहा है। पिछले तीन संस्करणों की सफलता के बाद यह आयोजन अब उत्तर प्रदेश के उत्पादों, सेवाओं, तकनीक और नवाचारों को वैश्विक बाजार से जोड़ने वाला एक प्रमुख मंच बन चुका है। इसके माध्यम से प्रदेश के उद्योग, एमएसएमई, स्टार्टअप और निर्यात क्षेत्र को नए अवसर मिलने की उम्मीद है। यूपीआईटीएस-2026 में 2400 से अधिक प्रदर्शकों के भाग लेने का अनुमान है, जबकि 85 देशों से 550 से अधिक अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के आने की संभावना है। इसके अलावा 1.50 लाख से अधिक घरेलू बी-टू-बी खरीदार और लगभग 4 .50 लाख आम नागरिकों की उपस्थिति का अनुमान लगाया गया है।

सीएम शुभेंदु अधिकारी ने शुरू की अन्नपूर्णा योजना, पहले चरण में 28 .25 लाख महिलाओं को मिलेंगे 3,000 ₹

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के पहले चरण में 28.25 लाख लाभार्थियों को 3,000 रुपये की मासिक सहायता मिलेगी। इसे बंगाल की भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी सामाजिक कल्याण योजना माना जा रहा है।

योजना के पहले चरण में लाभार्थियों के बैंक खातों में आज से सीधे 3,000 रुपये की राशि भेजी जाएगी। शुरुआती अनुमान के अनुसार, इस योजना से लगभग दो करोड़ महिलाओं को लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि, पहले चरण में 28.25 लाख महिलाओं को ही इसका लाभ मिलेगा।

बंगाल की पहली भाजपा सरकार की इस अन्नपूर्णा योजना के उद्घाटन समारोह में सीएम शुभेंदु अधिकारी के साथ महिला, बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पॉल भी मौजूद रहीं। योजना का उद्घाटन कार्यक्रम राज्य के सभी ब्लॉकों, नगरपालिकाओं और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में भी वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया।

लाभार्थियों को बांटे गए स्वीकृति पत्र उद्घाटन के तुरंत बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगरपालिका में चयनित 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे गए। इसी तरह कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में भी 100 लाभार्थियों को ये पत्र दिए गए। सूत्रों के अनुसार, संबंधित उपमंडल अधिकारियों (एसडीओ), बीडीओ और नगरपालिका प्रशासन की सिफारिशों के आधार पर लाभार्थियों की सूची को अंतिम रूप दिया गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से वित्तीय मदद मुहैया कराना है। इस वित्तीय मदद से वे अपने घरेलू खर्चों और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकेंगी। भाजपा के चुनावी घोषणापत्र में 'अन्नपूर्णा योजना' का एलान किया गया था। यह तृणमूल कांग्रेस सरकार की 'लक्ष्मी भंडार' योजना की जगह लेगी। लक्ष्मी भंडार योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने 1,500 रुपए मिलते थे।

'समझौते के बाद नहीं चलाया जा सकता क्रिमिनल केस', लोन डिफॉल्टरों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर बैंक और कर्जदार लोन खाते के निपटारे के लिए समझौता कर लेते हैं तो उसके बाद लोन डिफॉल्टर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती। अदालत ने चेतावनी दी कि ऐसी कार्यवाही को अनुमति देना न केवल दमनकारी होगा बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डालेगा।

जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने एक बिजनेसमैन की याचिका स्वीकार करते हुए उसके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले को रद्द कर दिया। बेंच ने कहा कि बैंकिंग लेन-देन मूल रूप से व्यावसायिक मामला होता है। जब दोनों पक्ष आपसी समझौते से विवाद सुलझा लेते हैं तो बाद में आपराधिक केस चलाना अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

इस मामले में बिजनेसमैन ने डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT) के सामने बैंक के साथ समझौता किया था। जिसमें 6.49 करोड़ रुपये के बकाया के मुकाबले 4.25 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया। जिसमें 3.09 करोड़ ब्याज की राशी थी।

समझौते के दो साल बाद बैंक ने धोखाधड़ी और जालसाजी का आपराधिक मामला दर्ज कराया। CBI ने जांच कर चार्जशीट दाखिल की, जिसमें आरोप लगाया गया कि बिजनेसमैन ने ऑडिट रिपोर्ट की जाली कॉपियों से कैश क्रेडिट लिमिट बढ़वाई थी। अदालत ने कहा, 'दोनों पक्षों के बीच विवाद खत्म हो चुका है। ऐसे में आरोपी के दोषी ठहराए जाने की संभावना न के बराबर है। केस जारी रखना अन्याय होगा।'

अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा असर

बेंच ने आगे कहा कि यदि DRT के सामने हुए समझौते के बाद भी आपराधिक कार्रवाई चलाने की इजाजत दी गई तो निपटारे का क्या? इससे व्यावसायिक संस्थाएं और उद्यमी बैंकिंग विवादों के समाधान से हिचकिचाएंगे, जिसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

शहर से ज्यादा ग्रामीण महिलाएं पीती हैं शराब, गोवा में सेवन करने वालों की संख्या हुई आधी

नई दिल्ली, एजेंसी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से पिछले दिनों जारी किए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2023-24 के अनुसार, शहरी क्षेत्रों की महिलाओं की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं ज्यादा शराब पीती हैं। साथ ही महिलाओं में शराब पीने की दर में मामूली गिरावट भी आई है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पुरुष भी ज्यादा शराब का सेवन करते हैं। जबकि अरुणाचल प्रदेश में पुरुषों और महिलाओं दोनों में शराब पीने की दर देश में सबसे अधिक दर्ज की गई है। सर्वे के अनुसार, देशभर में 15 साल या उससे अधिक की महिलाओं में शराब का सेवन करने की दर में थोड़ी गिरावट आई है। पिछले सर्वे (NFHS-5, 2019-21) की तुलना में महिलाओं की शराब पीने की दर गिरकर 1.1 फीसदी हो गई है, जबकि NFHS-5 की रिपोर्ट में यह दर 1.3 फीसदी थी। नए सर्वे में शहरी क्षेत्रों में जहां महज 0.5 फीसदी महिलाएं शराब पीती हैं तो ग्रामीण अंचल में यह दर 1.4 फीसदी तक पहुंच गया है।

गांव में शराब का सेवन अधिक

महिलाओं की तुलना में पुरुष कहीं अधिक शराब पीते हैं। पुरुषों में भी शराब पीने की दर बढ़ी है। NFHS-5 की रिपोर्ट में जहां देशभर में 18.7 फीसदी पुरुष शराब पीते थे, वहीं नई रिपोर्ट में यह दर बढ़कर 18.9 फीसदी हो गई है। शहरी क्षेत्र (15.5) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में 20.6 फीसदी पुरुष शराब पीते हैं। हालांकि तंबाकू खाने के मामले में महिलाओं की दर में गिरावट आई है। पिछले सर्वे में 8.9 फीसदी की तुलना में 8।.4 फीसदी महिलाएं ही तंबाकू का सेवन कर रही हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर 10 फीसदी है। 36.3 फीसदी पुरुष तंबाकू का सेवन करते हैं जिसमें 41 फीसदी से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं।

गोवा में शराब का सेवन घटा

पर्यटकों के लिहाज से पसंदीदा राज्य माने जाने वाले गोवा में शराब पीने की दर में गिरावट आई है। पिछले सर्वे की तुलना में महिलाओं ने शराब पीने की दर आधी से भी नीचे आ गई है। 15 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाओं में NFHS-5 सर्वे में शराब पीने की दर 5 .5 फीसदी थी, लेकिन नए सर्वे में यह दर आधी से कम होकर 2.1 फीसदी हो गई। पिछले सर्वे में 36 .8 फीसदी पुरुष शराब पीते थे तो नए सर्वे में 22 .4 फीसदी लोग ही शराब पीते हैं। यह सर्वे मुंबई स्थित अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS) की ओर से किया गया था, और इसमें देश के 715 जिलों के करीब 679,000 परिवारों को शामिल किया गया था।

यहां हर दूसरा नागरिक शराबी

NFHS-6 के सर्वे के अनुसार पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक शराब पी जाती है। यहां पर 15 साल और उससे अधिक आयु के 50.5 फीसदी पुरुष शराब का सेवन करते हैं। यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में सबसे अधिक दर है। हालांकि पिछले सर्वे की तुलना में इस बार इसमें थोड़ी गिरावट है। NFHS-5 में करीब 52.6 फीसदी लोग शराब पीते थे। सर्वे के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश की 15 साल और उससे अधिक आयु की महिलाएं सबसे अधिक शराब पीती हैं। अरुणाचल प्रदेश में देश में शराब के सेवन की दर सबसे अधिक (23.2 फीसदी) दर्ज की गई है। यह आंकड़ा पिछले सर्वे के 24.2 फीसदी से थोड़ा कम जरूर है, लेकिन राष्ट्रीय औसत से अभी भी काफी ज्यादा है।

NFHS-6 के नए आंकड़े दिखाते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर शराब के सेवन की दर पुरुषों में 18.9 फीसदी और महिलाओं में 1.1 फीसदी ही है। पुरुषों में सबसे अधिक शराब पीने के मामले में अरुणाचल प्रदेश के बाद तेलंगाना (43.9%) का नंबर आता है। फिर सिक्किम (42.2%), छत्तीसगढ़ (38.3%) और झारखंड (33.6%) आते हैं। तेलंगाना के ग्रामीण क्षेत्रों में 46.6 फीसदी पुरुष शराब पीते हैं।

जबकि महिलाओं में अरुणाचल प्रदेश के बाद सिक्किम का नंबर है। यहां पर 19.9 फीसदी महिलाएं शराब पीती हैं। इसके बाद तेलंगाना (7.1%), त्रिपुरा (6.0%) और असम (5.8%) का नंबर आता है।

ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्ति पर घमासान, हाईकोर्ट की चौखट पर यूपी सरकार का फैसला

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने का मामला अब हाईकोर्ट पहुंचा गया है। यूपी सरकार के प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चुनौती दी गई है। ओमप्रकाश प्रजापति द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से बुधवार (3 जून) को जवाब मांगा है।

याचिकाकर्ता ओमप्रकाश का दावा है कि यह आदेश पंचायती राज कानून की मंशा और स्थापित व्यवस्था के विपरीत है, इसलिए इसे रद्द किया जाए। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने शासनादेश और

संबंधित कानूनी प्रावधानों का जिक्र किया गया। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।मामले की सुनवाई 3 जून को होगी।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 12(3) (क) के अनुसार, ग्राम प्रधान का कार्यकाल शपथ ग्रहण की तिथि से अधिकतम पांच वर्ष का ही हो सकता है। ऐसे में समय पर पंचायत चुनाव न कराकर मौजूदा प्रधानों को ही प्रशासक बनाए रखना उनके कार्यकाल को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाने के समान है, जो कानून की मंशा के विपरीत है।

उन्होंने कहा कि पहले जब पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाते थे, तो ग्राम पंचायतों के संचालन के लिए एडीओ पंचायत या अन्य सरकारी अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त किया जाता था। उन्होंने कहा कि इस बार भी किसी सक्षम सरकारी अधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया जाना चाहिए, न कि उन ग्राम प्रधानों को जिनका वैधानिक कार्यकाल समाप्त हो चुका है।

पुरानी परंपरा

अब तक परंपरा के तहत ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने पर एडीओ पंचायत को प्रशासक बनाया जाता था, लेकिन इस बार व्यवस्था बदली गई।पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होने की संभावना के बीच यह फैसला राजनीतिक और कानूनी बहस का विषय बन गया है।

कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

ओमप्रकाश के वकील अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने बताया, कोर्ट ने इस मामले में पेश हुए सरकारी वकील को राज्य सरकार से निर्देश लेकर बुधवार को अपना पक्ष पेश करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति शेखर बी। सराफ और न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी की बेंच ने निर्देश लेकर पक्ष रखने का आदेश दिया है।

क्या है मामला

दरअसल ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद यूपी सरकार ने उन्हें ही उनकी पंचायतों में 6 महीने के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिया। आदेश के तहत बुधवार से प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधान प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे। यूपी की सभी 57 हजार 694 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो गया था। इससे एक दिन पहले 25 मई को योगी सरकार ने यूपी में पंचायत चुनाव होने या अगले 6 महीने तक ग्राम प्रधानों को प्रशासक बना दियाय

सरकार का कहना है कि पंचायत चुनाव में देरी और पिछड़ा वर्ग आरक्षण प्रक्रिया लंबी होने के कारण यह फैसला लिया गया है। सरकार के अनुसार इससे सफाई, पेयजल, मनरेगा, सड़क मरम्मत और अन्य विकास कार्य बिना रुकावट जारी रहेंगे। आदेश में कहा गया था कि प्रशासक यानी ग्राम प्रधान अपने स्तर पर कोई बड़ा या नीति से जुड़ा फैसला नहीं ले सकेगा। अगर किसी जरूरी या विशेष स्थिति में ऐसा फैसला लेना जरूरी हो, तो उसका प्रस्ताव जिला पंचायत राज अधिकारी के जरिए जिलाधिकारी को भेजा जाएगा। जिलाधिकारी की मंजूरी मिलने के बाद ही उस पर फैसला लिया जाएगा।

सेवानिवृत्त वनरक्षक पर मुकदमा दर्ज, वायरल ऑडियो से मचा हड़कंप

बल्दीराय/सुल्तानपुर। जनपद में वन विभाग और पुलिस महकमे में उस समय हलचल मच गई जब सोशल मीडिया पर वायरल एक ऑडियो के आधार पर सेवानिवृत्त वनरक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह के विरुद्ध बल्दीराय थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। मामला सामने आने के बाद विभागीय कार्यप्रणाली, वन संरक्षण और अवैध कटान के खिलाफ चल रही कार्रवाई एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई है। उपक्षेत्रीय वन अधिकारी बृजेश कुमार यादव द्वारा दर्ज कराई गई तहरीर में आरोप लगाया गया है कि अवैध महुआ कटान तथा अवैध आरा मशीनों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई से नाराज होकर वायरल ऑडियो में उनके प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। साथ ही जूतों से मारने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई। अधिकारी ने अपनी तथा अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर आशंका व्यक्त करते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी।

24 घंटे में लूटकांड का खुलासा, दो शातिर बदमाश गिरफ्तार

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। जिले की धम्मौर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए गैस सिलेंडर डिलीवरी वैन के सेल्समैन से हुई लूट की वारदात का महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के अनुसार बदमाशों ने गैस सिलेंडर डिलीवरी वैन के सेल्समैन से 9100 रुपये नगद और मोबाइल फोन लूट लिया था। घटना के बाद धम्मौर पुलिस ने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए जांच शुरू की और मुखबिर की सूचना व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंच गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उघरपुर निवासी सत्येन्द्र प्रताप सिंह तथा बदौलिया निवासी विशद मिश्रा के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई नकदी, मोबाइल फोन और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। पुलिस के अनुसार, आरोपी विशद मिश्रा के खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। धम्मौर पुलिस की त्वरित और प्रभावी कार्रवाई से लूट की वारदात का पर्दाफाश हो गया और दोनों बदमाश सलाखों के पीछे पहुंच गए।

वन विभाग में तबादला नीति पर भारी स्थायी तैनाती, वर्षों से जमे कर्मचारियों पर उठे सवाल

बल्दीराय/सुल्तानपुर। वन विभाग में तबादला नीति और शासनादेशों की अनदेखी को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। विभाग के कई कर्मचारी और अधिकारी वर्षों से एक ही क्षेत्र अथवा अपने गृह क्षेत्र में तैनात हैं, जिससे विभागीय कार्यप्रणाली की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लग रहा है। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे कर्मचारियों के कारण पारदर्शिता प्रभावित हो रही है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। प्रदेश सरकार समय-समय पर तबादला नीति जारी कर अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्धारित अवधि के बाद स्थानांतरित करने के निर्देश देती है। नीति का उद्देश्य स्थानीय प्रभाव, पक्षपात और भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम करना होता है। इसके बावजूद वन विभाग में कई ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जो वर्षों से एक ही क्षेत्र में कार्यरत बताए जा रहे हैं।

नशा, कलह और मौत : शराब पीकर पड़ा था पति, मौत से जुझ रहे थे पत्नी–बच्चे, फिर चढ़ गई मासूम की बलि

आर्यावर्त संवाददाता

फतेहपुर। फतेहपुर जिले में नशे के लती पति से तंग आकर महिला ने खेत में दो बच्चों समेत जहर खा लिया और तीसरे बच्चे को जहर देने की कोशिश की, लेकिन वह मौके से भाग निकला। उसने परिजन व ग्रामीणों को घटना की जानकारी दी। परिजन ने महिला और दोनों बच्चों को सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने छह वर्षीय बच्चे को मृत घोषित कर दिया।

वहीं, महिला और उसके एक वर्षीय पुत्र को कानपुर रेफर किया गया है। थाना क्षेत्र के गांव धौरहारा निवासी रज्जन निषाद शराब का लती है। घर में पत्नी राजकली (30), पुत्री शिवानी (10), पुत्र शिवा (8), छोटू उर्फ राज (6), सौरभ (1) हैं। रज्जन नशे में अक्सर पत्नी-बच्चों को गाली-गलौज व पिटाई करता है। दोनों के बीच मंगलवार को भी विवाद हुआ। इसके बाद राजकली घर से छोटू व सौरभ को लेकर करीब 100

मीटर दूर खेत पहुंची। साथ में वह पानी की बोतल, गिलास व जहर ले गई थी। महिला ने पानी में घोलकर पहले बच्चों को जहर दिया और फिर खुद पी लिया। घटना के समय शिवानी घर में नहीं थी। घटनास्थल से कुछ दूरी पर यमुना नदी से शिवा नहाकर घर लौट रहा था।

राजकली ने शिवा को भी पास बुलाकर जहर पिलाने का प्रयास किया, लेकिन वह वहां से भाग निकला और पड़ोसियों और परिजन को जानकारी दी। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने राजकली और बेटों को तड़पता देखकर सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने छोटू को मृत घोषित कर दिया।

दोनों गंभीर हालत में कानपुर रेफर

राजकली और सौरभ की हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया, जहां से दोनों को कानपुर हैलट रेफर किया। प्रभारी थानाध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला घरेलू कलह से जुड़ा है। घटना की जांच की जा रही है। बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

मायके पक्ष ने कराया था समझौते का प्रयास

रज्जन के नशे का लती होने की वजह से घर में आए दिन कलह रहती थी। कुछ समय पहले थानाक्षेत्र के ही मंसूरपुर गांव से राजकली के मायके पक्ष से परिजन प्रधान को लेकर घर पहुंचे थे। उस दौरान प्रधान ने रज्जन को समझाने का प्रयास किया था। साथ ही मायके पक्ष के लोग राजकली को अपने साथ ले गए थे। बच्चों के मोह के चलते वह कुछ दिन बाद ससुराल लौट आई थी। इसके बाद भी पति-पत्नी के बीच विवाद समाप्त नहीं हुआ था। ग्रामीण महिलाओं में चर्चा रही कि राजकली ने सोचा होगा कि उसके मारने के बाद मासूम बच्चों क्या होगा, इसी वजह से बच्चों के साथ जान देने का प्रयास किया।

घटना के दौरान नशे में पड़ा रहा रज्जन

ग्रामीणों ने बताया कि घटना के वक्त रज्जन निषाद नशे में ही घर में पड़ा रहा जबकि पूरे गांव में घटना से खलबली मची हुई थी। ग्रामीणों के अनुसार रज्जन पहले गोवा में नौकरी करता था। वहां एक पैर में कुछ तकलीफ होने के कारण नौकरी छोड़कर दो वर्ष पहले गांव लौट आया था। गांव में रहने के दौरान दिन-रात शराब पीने लगा था।

प्रयागराज हत्याकांड का खुलासा, बेटे ने पड़ोसी दुकानदार के साथ मिलकर रची साजिश और खुद भी मारा गया

डेढ़ करोड़ रुपये के आभूषण लूटे

अलमारी में रखे करीब डेढ़ करोड़ रुपये के आभूषण लूट लिया। दोनों नीचे दुकान में आए और यहां आभूषणों का बंटवारा करने लगे। अभिषेक ने सनी को थोड़े ही आभूषण दिए, जिसे लेकर दोनों में विवाद शुरू हो गया। इसी बीच सनी बाहर निकला और लोहे की रॉड लेकर आया। अचानक उसने अभिषेक के सिर पर प्रहार कर दिया। एक के बाद एक कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसके चेहरे पर केमिकल डाला और भाग निकला।

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

प्रयागराज। कोतवाली थाना क्षेत्र के साउथ मलाका चौराहे पर हुई व्यवसायी 70 वर्षीय वीरेंद्र वैश्य, 65 वर्षीय उनकी पत्नी अनीता, 40 वर्षीय पुत्री मीनाक्षी व 38 वर्षीय पुत्र अभिषेक की हत्या का राजफाश पुलिस ने कर दिया है।

मकान के ग्राउंड फ्लोर में समोसा-पकौड़ा की दुकान चलाने वाले सनी गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पूछताछ में उसने बताया कि अभिषेक से उसकी दोस्ती थी और संपत्ति व रुपये के लालच में उसने वारदात को अंजाम दिया।

पहले अभिषेक के साथ मिलकर उसके माता-पिता व बहन को मौत के घाट उतारा और लूट के डेढ़ करोड़ के आभूषण के बंटवारे को लेकर अभिषेक की हत्या कर दी। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड को भी बरामद कर लिया है। वीरेंद्र वैश्य अपने एक पुत्र अश्वनी को पहले ही संपत्ति से बेदखल कर चुके थे। दूसरे पुत्र अभिषेक की भी आदत ठीक नहीं थी, जिस कारण उसे भी बेदखल करने की धमकी देते थे। पूरी संपत्ति वह अविवाहित पुत्री मीनाक्षी को देने की बात करते थे।

इससे अभिषेक और उसके पिता के बीच विवाद होता था। अभिषेक को लगता था कि अश्वनी की तरह ही उसे भी कहीं अगर पिता ने बेदखल कर दिया तो वह कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए उसने पड़ोस में दुकान चलाने वाले सनी गुप्ता निवासी मुट्ठीगंज से मेलजोल बढ़ाया। रविवार दोपहर उसने सनी को अपनी दुकान में बुलाया। दोनों ने यहां बैठकर बातचीत की। इसके बाद दिन ढलते ही दूसरी मंजिल पर जाकर वीरेंद्र, अनीता व मीनाक्षी के सिर पर लोहे के रॉड से प्रहार कर हत्या कर दी। मंगलवार देर रात पुलिस ने जब सनी गुप्ता को पकड़ा और पूछताछ की तो यह सारी कहानी सामने आई। सनी ने पुलिस को बताया कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह अमीर बनना चाहता था। अभिषेक ने उसे लूट के आभूषणों के साथ ही संपत्ति में भी कुछ हिस्सा देने की बात कही थी, जिस लालच में वह आ गया।

बालू व्यवसायी की पत्थर से सिर कूंचकर हत्या

प्रयागराज। घूरपुर थाना क्षेत्र के भीटा गांव में बुधवार भोर में एक बालू व्यवसायी की पत्थर से सिर कूंचकर हत्या कर दी गई। सुबह 5 बजे परिजनों ने उसे मृत पाया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार घूरपुर के भीटा गांव निवासी 32 वर्षीय राजेश कुमार प्रजापति पुत्र अगम लाल बालू व्यवसायी थे। वह अपनी ही ट्रक से बालू सप्लाई का काम करते थे। मंगलवार देर रात वह अपने घर के बाहर सड़क किनारे एक छप्पर के नीचे सोए थे। परिजनों के अनुसार, बुधवार सुबह 5 बजे जब उन्होंने राजेश को देखा तो उनका सिर बड़े पत्थर से कुचला हुआ था और घटनास्थल पर खून बिखरा था। राजेश अपने तीन भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके परिवार में पत्नी पार्वती देवी और एक बेटा-बेटी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि राजेश का स्वभाव मिलनसार था और उनकी किसी से खुली रंजिश की जानकारी नहीं है।

डाक व्यवस्था भगवान भरोसे, सर्वर बैठा तो व्यवस्था भी बैठ गई

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। जिले के प्रधान डाकघर समेत बस स्टैंड, सिविल लाइन, करौंदिया व अन्य उपडाकघरों में बुधवार सुबह से नेट और सर्वर फेल होने के कारण करोड़ों रुपये का लेन-देन पूरी तरह ठप्प रहा। घंटों इंतजार के बाद लोग मायूस होकर लौटते नजर आए, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी पूरे मामले पर मौन साधे रहे।

आलम यह रहा कि पासबुक अपडेट, पैसा जमा-निकासी, स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री समेत तमाम सेवाएं बंद पड़ी रहीं। डिजिटल इंडिया के दावों के बीच डाकघरों की व्यवस्था खुद नेटवर्क तलाशती दिखाई दी। विडंबना यह है कि जिन उपडाकघरों को आम जनता की सुविधा का केंद्र माना जाता है, वहां वर्षों से मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। न पीने के पानी की व्यवस्था, न बैठने की सुविधा। बिजली चली जाए तो पूरा सिस्टम ऐसे ठप्प हो जाता है मानो

इमारत नहीं, किसी पुराने जमाने का बंद पड़ा गोदाम हो। न जनरेटर, न इन्वर्टर, यहां तक कि मोमबत्ती और लालटेन तक की व्यवस्था नहीं। किवंदंतियों में जरूर कहा जाता है कि भारत की डाक व्यवस्था एशिया का सबसे बड़ा जनसंपर्क नेटवर्क है, लेकिन जमीनी हकीकत देखकर लोग यही कहते नजर आए कि यह व्यवस्था अब इतिहास की किताबों में ही बेहतर लगती है। जनता का सवाल सीधा है कि जब बैंकिंग, बीमा और सरकारी योजनाओं का इतना बड़ा भार डाक विभाग उठा रहा है, तो आखिर सुविधाओं और तकनीकी व्यवस्था के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही क्यों? फिलहाल सर्वर डाउन है, व्यवस्था डाउन है और जनता का भरोसा भी धीरे-धीरे डाउन होता जा रहा है।

IIT ग्रेजुएट, 20 लाख का पैकेज... नौकरी छोड़ हाई–प्रोफाइल लड़कियों को बनाने लगा टारगेट, ढोंगी बाबा अभिषेक मिश्रा के घिनौने खेल की अनसुनी कहानी

ब्लैकमेलिंग के पैसों से बनाया आश्रम

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी इन अश्लील वीडियो और तस्वीरों के बल पर पीड़ित युवतियों से मोटी रकम वसूलता था। इसी ब्लैकमेलिंग से ऐंठे गए पैसों से उसने राधाकुंड में एक मकान खरीदा और उसे अपने आश्रम का रूप दे दिया। हद तो तब हो गई जब आरोपी ने अपनी सगी मां (जो ओडिशा सरकार में सरकारी टीचर थीं और रिटायरमेंट के बाद उसके साथ रह रही थीं) के विरोध करने पर उनके साथ बेरहमी से मारपीट की और उन्हें घर से भगा दिया।

आर्यावर्त संवाददाता

मथुरा। धर्मनगरी मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र से पुलिस ने एक ऐसे शातिर और पाखंडी बाबा को गिरफ्तार किया है, जिसकी हकीकत जानकर हर कोई दंग है। खुद को आध्यात्मिक गुरु बताने वाला यह शख्स असल में एक हाई-एजुकेटेड क्रिमिनल है, जो ऑनलाइन प्रवचन और भजन-कीर्तन के जाल में पढ़ी-लिखी और बड़े पैकेजों पर काम करने वाली युवतियों को फंसाता था। इसके बाद उन्हें नशीला पदार्थ देकर उनका शारीरिक शोषण करता और अश्लील वीडियो बनाकर लाखों रुपये ब्लैकमेल करता था। पुलिस ने आरोपी अभिषेक मिश्रा उर्फ अधिकारता नारायण दास को राधाकुंड स्थित उसके कथित आश्रम से गिरफ्तार कर लिया है। मौके से दो युवतियों और एक लड़के को सुरक्षित मुक्त कराया गया है।

एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत के मुताबिक, आरोपी अभिषेक मिश्रा मूल रूप से ओडिशा का रहने वाला है। उसने साल 2017 से 2021 के बीच देश के प्रतिष्ठित संस्थान IIT रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था। इसके बाद उसने मुंबई की एक बड़ी कंपनी में 20 लाख रुपये के सालाना पैकेज पर नौकरी भी की। लेकिन साल 2023 में वह नौकरी छोड़कर मथुरा के राधाकुंड इलाके में आ गया और यहां किराए का कमरा लेकर रहने लगा।

अभिषेक बेहद पढ़ा-लिखा था, इसलिए उसकी बातचीत का तरीका काफी प्रभावी था। उसने गीता पर ऑनलाइन प्रवचन देना शुरू किया। उसका मुख्य टारगेट मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs) में काम करने वाली हाई-प्रोफाइल और पढ़ी-लिखी युवतियां होती थीं। वह ऑनलाइन माध्यम से युवक-युवतियों का इस कदर ब्रेनवॉश करता कि वे सब कुछ छोड़कर उसके पास गोवर्धन आ जाते। वहां वह लड़कों का लड़कियों से गंधर्व विवाह करा देता और फिर जाल में फंसाकर लड़कियों का खुद शोषण करने लगता।

छत्तीसगढ़ की छात्रा ने दिखाई हिम्मत, ऐसे खुला राज

इस पूरे सनसनीखेज मामले का खुलासा तब हुआ जब छत्तीसगढ़ की रहने वाली बीएससी नर्सिंग की एक छात्रा अपनी बहन से मिलने मथुरा आई थी। 15 मई की रात आरोपी अभिषेक ने उसे प्रसाद के नाम पर दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और उसके साथ घिनौनी हरकत की। जब पीड़िता अपने घर लौटी और माता-पिता को आपबीती बताई, तो उसके पिता उसे लेकर मथुरा के एसएसपी श्लोक कुमार के पास पहुंचे।

एसएसपी के निर्देश पर 25 मई को गोवर्धन थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि आरोपी अब तक करीब 12 दर्जन (144) युवक-युवतियों का ब्रेनवॉश कर चुका है और दो दर्जन से अधिक लोग उसके चंगुल में फंसे हुए थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे सिंडिकेट और नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है।

गिरीश चंद्र यादव बने जिले के प्रभारी मंत्री

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने आखिरकार सुल्तानपुर में बड़ा राजनीतिक फेरबदल कर ही दिया। खेल एवं युवा कल्याण राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव को जिले का नया प्रभारी मंत्री बना दिया गया, जबकि अब तक यह जिम्मेदारी संभाल रहे ओम प्रकाश राजभर को अंबेडकर नगर भेज दिया गया है। सत्ता के गलियारों में इसे सामान्य प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि भाजपा की डैमेज कंट्रोल रणनीति माना जा रहा है। चर्चा यह है कि प्रभारी मंत्री की कुर्सी पर बैठकर ओम प्रकाश राजभर सरकार की नीतियों को धरातल पर उतारने से ज्यादा अपनी पार्टी सुभासपा को मजबूत करने में जुटे थे। सुल्तानपुर में विकास योजनाओं और संगठनात्मक समन्वय से ज्यादा राजनीतिक जोड़तोड़ की चर्चा रही। हाल ही में जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा सिंह के पति व बल्दीराय ब्लॉक प्रमुख शिव कुमार सिंह को भाजपा से तोड़कर सुभासपा में शामिल कराना इसी रणनीति का हिस्सा माना गया। राजनीतिक जानकार तंज कस रहे हैं कि प्रभारी मंत्री की जगह राजभर भर्ती मंत्री की भूमिका में नजर आ रहे थे कृ जहां सरकारी बैठकों से ज्यादा फोकस अपनी पार्टी के लिए जमीन तैयार करने पर दिखा। खासतौर पर इसौली विधानसभा सीट पर सुभासपा की सक्रियता ने भाजपा संगठन की चिंता बढ़ा दी थी। 2022 में भाजपा इसौली सीट महज 300 वोटों से हारी थी। ऐसे में भाजपा को डर था कि अगर सहयोगी दल ही उसी सीट पर अपनी दावेदारी मजबूत करने लगे तो आने वाले विधानसभा चुनाव में नुकसान तय हो सकता है। यही वजह रही कि संगठन से जुड़े नेताओं और विधायकों ने पार्टी नेतृत्व तक यह संदेश पहुंचाया कि सुल्तानपुर में सरकार कम, सुभासपा ज्यादा" दिखाई दे रही है।

150 फरियादियों से मिले सीएम योगी, अफसरों को निर्देश- लापरवाही पर अपनाएं सख्त रुख

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में भूमि संबंधी शिकायतों पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने डीएम को निर्देशित किया कि भूमि संबंधी शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए।

प्रकरण की गंभीरता के अनुसार संबंधित के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाए। किसी भी स्तर पर शिथिलता या लापरवाही कतई क्षम्य नहीं है। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। कुछ लोगों ने जमीन से जुड़े मामलों में राजस्व कर्मियों की तरफ से लापरवाही किए जाने की शिकायत की तो उन्होंने डीएम को तत्काल कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। इस अवसर पर इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे लोगों से उन्होंने कहा कि सरकार इलाज में पूरी मदद करेगी। इसके लिए जरूरतमंद लोगों का आयुष्मान कार्ड बनवाया जाएगा और इसके बाद भी जरूरत पड़ी तो विवेकाधीन कोष से सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर जरूरतमंद, पात्र व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि उन्हें इलाज के लिए परेशान न होना पड़े। गोरखनाथ मंदिर परिसर में महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी करीब 150 लोगों से मिले। उनके पास जाकर उनकी समस्याएं सुनीं। उनके प्रार्थना पत्रों का अवलोकन कर समस्या, शिकायत का संज्ञान लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिया कि किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है। एक महिला ने कुछ लोगों द्वारा मकान से बेदखल किए जाने की शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा कि मकान पर महिला का कब्जा दिलाया जाए। उन्होंने अलग-अलग मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र संदर्भित करते हुए निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और संतुष्टिप्रद होना चाहिए।

जनता दर्शन में एक महिला ने मां के इलाज के लिए सहायता देने का निवेदन किया। मुख्यमंत्री ने आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा। महिला ने बताया कि उसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। इस पर सीएम ने मौके पर मौजूद अफसरों को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द इनका आयुष्मान कार्ड बनवाया जाए। अधिकारी हर जरूरतमंद का आयुष्मान कार्ड बनवाएं, ताकि उन्हें इलाज के लिए परेशान न होना पड़े। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर आए लोगों को मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि उन्हें विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

गोसेवा की और बच्चों पर प्यार लुटाया सीएम योगी ने

गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान बुधवार सुबह भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या परंपरागत रही। प्रातःकाल गुरु गोरखनाथ और अपने ब्रह्मलीन गुरुदेव महंत अवेद्यनाथ जी का आशीर्वाद लेने के बाद सीएम योगी ने मंदिर की गोशाला में गोसेवा की।

युवक पर जानलेवा हमले के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार, अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। अलीगंज थाना क्षेत्र में युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने और मारपीट के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक के कब्जे से अवैध पिस्टल और चार जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने मामले में आर्म्स एक्ट की धाराएं बढ़ाते हुए आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार सेक्टर-बी, अलीगंज निवासी यशराज सिंह ने 2 जून 2026 को थाना अलीगंज में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि कुछ लोगों ने उनके साथ धारदार हथियार से हमला किया, मारपीट की और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने का प्रयास किया। शिकायत के आधार पर सलमान खान, सौरभ यादव, हेमंत वर्मा, आकाश वाल्मीकि, रितिक सिंह, विशाल सिंह तथा अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया।मामले की विवेचना के दौरान 3 जून को अलीगंज पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश में कपूरथला क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि नगर निगम सेक्टर-बी के पास हुई मारपीट की घटना में शामिल कुछ आरोपी एमजी कॉलोनी सेक्टर-सी रेलवे लाइन की ओर से आ रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की तो बाइक सवार दो युवक भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दबोच लिया।

पूछताछ में आरोपियों ने अपनी पहचान आकाश कुमार वाल्मीकि (22) निवासी प्रगति नगर, तकरोही और सलमान खान (26) निवासी इस्माइलगंज, लखनऊ के रूप में बताई। दोनों आरोपी मुकदमे में नामजद वांछित थे।तलाशी के दौरान आकाश कुमार वाल्मीकि के पास से 180 रुपये नकद बरामद हुए, जबकि सलमान खान के कब्जे से एक अवैध .32 बोर पिस्टल और चार जिंदा कारतूस मिले। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 भी जोड़ी गई।पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी जिस मोटरसाइकिल से आए थे, वह यूपी-65-सीए-3224 नंबर की थी। पूछताछ में सलमान ने बताया कि मोटरसाइकिल उसके मित्र की है। पुलिस ने वाहन को मोटर वाहन अधिनियम के तहत सीज कर दिया है।पुलिस के अनुसार मामले में सौरभ यादव, हेमंत वर्मा, रितिक वाल्मीकि और विशाल सिंह समेत अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।पुलिस अभिलेखों के अनुसार गिरफ्तार आरोपी सलमान खान के विरुद्ध पूर्व में भी हसनगंज थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है। दोनों गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, जबकि शेष आरोपियों की तलाश जारी है।

संक्षेप

दुष्कर्म के आरोप में दो आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा

लखनऊ। जानकीपुरम थाना क्षेत्र में एक किशोरी के साथ कथित दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) एवं पॉक्सो अधिनियम की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार 2 जून 2026 को पीड़िता की मां ने थाना जानकीपुरम में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उसकी लगभग 15 वर्षीय पुत्री, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, को दिनेश नामक व्यक्ति तथा उसके एक साथी ने एक खाली मकान में रातभर बंद रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 101/2026 धारा 64(2), 70(2), 127(2) बीएनएस तथा 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया।मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पीड़िता और वादिनी के बयान दर्ज किए, घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा चिकित्सीय परीक्षण कराया। साथ ही सीसीटीवी फुटेज और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों का संकलन भी किया गया। घटना के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया।

मुरादाबाद में 4 जून को होगी रालोद की विजय संकल्प महारैली, जयंत सिंह करेंगे संबोधित

लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) द्वारा 4 जून को जनपद मुरादाबाद में विजय संकल्प महारैली का आयोजन किया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय कौशल विकास मंत्री चौधरी जयंत सिंह इस रैली को संबोधित करेंगे। रालोद ने दावा किया है कि यह रैली मुरादाबाद के राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी सभाओं में से एक होगी।राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे ने बताया कि ठाकुरद्वारा स्थित सनातन धर्म हिन्दू इंटर कॉलेज मैदान में दोपहर 2 बजे से आयोजित होने वाली इस महारैली की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर किसानों, मजदूरों और युवाओं से संपर्क कर रहे हैं तथा उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को पुनः सत्ता में लाने के उद्देश्य से प्रदेशव्यापी अभियान शुरू कर दिया है। इसी क्रम में चौधरी जयंत सिंह मुजफ्फरनगर, शामली, अमरोहा, मेरठ और सहारनपुर में विजय संकल्प रैलियों को संबोधित कर चुके हैं और अब उनका अगला पड़ाव मुरादाबाद होगा।

मनरेगा से गांवों में संवर रही खेल प्रतिभाएं, प्रदेश में 5 हजार से अधिक खेल मैदानों का निर्माण

लखनऊ, 3 जून। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और खेलों के लिए आधारभूत सुविधाओं को मजबूत बनाने की दिशा में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व एवं निर्देशन में मनरेगा योजना के तहत गांवों में खेल मैदान, स्टेडियम, ओपन जिम और पार्क विकसित किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण युवाओं को अपने ही क्षेत्र में खेल प्रशिक्षण और अभ्यास की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं।उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना है। गांवों में विकसित हो रहे खेल मैदान युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित कर रहे हैं और उन्हें राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांवों की प्रतिभाएं भविष्य में देश का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगी।मनरेगा के तहत निर्मित खेल मैदानों में रनिंग ट्रैक सहित विभिन्न सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इससे सेना, अर्द्धसैनिक बलों, पुलिस, सीआरपीएफ तथा अन्य सेवाओं की तैयारी करने वाले ग्रामीण युवाओं को अपने गांव में ही अभ्यास का अवसर मिल रहा है। खेल मैदानों के निर्माण से युवाओं को दौड़ और शारीरिक प्रशिक्षण के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध हो रहा है।

स्वच्छ सर्वेक्षण-2026 की तैयारियों की समीक्षा, महापौर ने सफाई और जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए निर्देश

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। स्वच्छ सर्वेक्षण-2026 की तैयारियों के तहत महापौर सुषमा खर्कवाल ने नगर आयुक्त गौरव कुमार के साथ जोन-5 कार्यालय में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में स्वच्छता व्यवस्था, डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण, नाला-नाली सफाई, जल निकासी, अतिक्रमण नियंत्रण, स्ट्रीट लाइट, राजस्व वसूली तथा नागरिक सुविधाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।बैठक में भाजपा पार्षद दल के उपनेता सुशील तिवारी 'पम्मी', पार्षद पीयूष दीवान, जितेंद्र सिंह 'जीतू', नरेंद्र कुमार, नामित पार्षद संतोष सिंह बलखंडी सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। अधिकारियों में अपर नगर आयुक्त अभिनव रंजन श्रीवास्तव, जोनल अधिकारी विनीत सिंह, जीएम जलकल कुलदीप सिंह तथा अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।महापौर ने निर्देश दिए कि स्वच्छ सर्वेक्षण-2026 को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वार्ड में सफाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने तथा स्वच्छता कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए।मानसून की तैयारियों की समीक्षा करते हुए महापौर ने नालों, नालियों और चैंबरों की सफाई समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराने पर जोर दिया। उन्होंने जलभराव संभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर आवश्यक संसाधनों और मानवबल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि वर्षा ऋतु में नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं और सुझावों से अधिकारियों को अवगत कराया। महापौर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए और उसकी नियमित समीक्षा भी की जाए। महापौर ने सार्वजनिक स्थलों, सड़कों और बाजारों में अतिक्रमण के विरुद्ध नियमित अभियान चलाने के निर्देश देते हुए कहा कि यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और नागरिकों की सुविधा के लिए प्रभावी कार्रवाई आवश्यक है। इसके साथ ही पेयजल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट और अन्य नागरिक सुविधाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने शिकायतों के त्वरित निस्तारण और विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया।बैठक के अंत में महापौर ने अधिकारियों को स्वच्छता, जल निकासी, अतिक्रमण नियंत्रण एवं जनसुविधाओं से जुड़े कार्यों की नियमित निगरानी करने तथा अगली समीक्षा बैठक में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

राजाजीपुरम में तेज रफ्तार डीसीएम की टक्कर से युवक की मौत, चालक और वाहन पुलिस हिरासत में

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। राजधानी के तालकटोरा थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। राजाजीपुरम स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिग्री कॉलेज के पास तेज रफ्तार डीसीएम वाहन की टक्कर से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, लेकिन युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी थी। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल वाहन और उसके चालक को हिरासत में लेकर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार 2 जून 2026 की रात करीब 11:15 बजे थाना तालकटोरा को सूचना मिली कि ई-ब्लॉक, राजाजीपुरम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिग्री कॉलेज के पास एक डीसीएम वाहन संख्या यूपी-32 डब्ल्यूएन-2546 ने सड़क पर पैदल जा रहे एक युवक को टक्कर मार दी है। हादसा इतना गंभीर था कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।सूचना प्राप्त होते ही प्रभारी निरीक्षक तालकटोरा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और आवश्यक जांच शुरू की। मौके पर मौजूद लोगों से जानकारी लेने के साथ ही घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए गए। जांच के दौरान मृतक की पहचान सुभाष कनौजिया उर्फ मिंकू (22) पुत्र कन्नू प्रसाद कनौजिया के रूप में हुई। वह मूल रूप से गोण्डा जनपद के उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र के ग्राम कुमेदानी का निवासी था और वर्तमान में हैदर कैनाल के पास झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र में रहकर जीविकोपार्जन कर रहा था।पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुर्घटना में शामिल डीसीएम वाहन और उसके चालक को मौके से कब्जे में लेकर थाने पहुंचाया।

मड़ियांव में बीकॉम छात्र ने फांसी लगाकर दी जान, पुलिस जांच में जुटी

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। मड़ियांव थाना क्षेत्र के भरतनगर इलाके में रहने वाले एक 24 वर्षीय छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की बात सामने आई है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।पुलिस के अनुसार 2 जून 2026 को शाम करीब 4:50 बजे बीकेटी स्थित सौ शैय्या अस्पताल से डेथ मेमो प्राप्त हुआ। अस्पताल प्रशासन ने सूचना दी कि महेन्द्र कुमार (24) पुत्र देवी प्रसाद को उसी दिन सुबह लगभग 3:40 बजे मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को सुरक्षित रूप से शवगृह में रखवाया गया।सूचना मिलते ही थाना मड़ियांव पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में पता चला कि महेन्द्र कुमार भरतनगर क्षेत्र में अपने भाई के साथ किराये के मकान में रहता था। वह मूल रूप से बाराबंकी जनपद के कुर्सी थाना क्षेत्र स्थित ग्राम मोहसंड का निवासी था और बीकॉम का छात्र था।पुलिस जांच में यह तथ्य सामने आया कि युवक ने अपने कमरे में पंखे के कुंडे से रस्सी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस परिजनों और अन्य संबंधित लोगों से जानकारी जुटा रही है। पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। अधिकारियों के अनुसार मामले में अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा सभी पहलुओं की जांच जारी है।पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

भांजे की हत्या कर केले के खेत में फेंका शव, एक दिन में आरोपी मामा गिरफ्तार

लखनऊ। इटौंजा थाना क्षेत्र में 22 वर्षीय युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पारिवारिक विवाद और अपनी बहन के प्रति मृतक की कथित गलत नीयत से नाराज होकर युवक की गला दबाकर हत्या कर दी थी और शव को केले के खेत में फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त प्लास्टिक स्ट्रेप भी बरामद कर ली है।पुलिस के मुताबिक 2 जून 2026 को इन्द्रपुरी कॉलोनी, मड़ियांव निवासी राम शंकर सिंह ने थाना इटौंजा में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनके 22 वर्षीय पुत्र सचिन सिंह को एक व्यक्ति घर से बुलाकर अपने साथ ले गया और उसकी हत्या कर दी। शिकायत के आधार पर थाना इटौंजा में हत्या का मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

पेप्सिको इंडिया ने लॉन्च किया प्रीमियम एनर्जी ड्रिंक 'एड्रेनलिन रश'

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। पेप्सिको इंडिया ने अपने प्रीमियम अंतरराष्ट्रीय एनर्जी ड्रिंक ब्रांड 'एड्रेनलिन रश' को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। इसके साथ ही कंपनी ने 'ए-रश, ए-गेम ऑन' अभियान भी शुरू किया है, जिसके तहत एक नई प्रचार फिल्म जारी की गई है। कंपनी का कहना है कि यह लॉन्च उसके एनर्जी ड्रिंक्स पोर्टफोलियो के विस्तार और युवा उपभोक्ताओं की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।पेप्सिको इंडिया की एनर्जी ड्रिंक्स श्रेणी प्रमुख दीक्षा बजाज ने कहा कि एड्रेनलिन रश को नई पीढ़ी के उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह ब्रांड जुनून, प्रदर्शन और लक्ष्य हासिल करने की भावना को दर्शाता है। उनके अनुसार यह अभियान उस पीढ़ी की सोच को सामने लाता है जो लगातार अपनी सीमाओं को चुनौती देते हुए बेहतर प्रदर्शन की ओर बढ़ रही है।पेप्सिको इंडिया के इंडिया बिजनेस यूनिट बेवरेजेज के मुख्य विपणन अधिकारी तरुण भगत ने कहा कि भारत में एनर्जी ड्रिंक्स बाजार लगातार बढ़ रहा है और उपभोक्ता अपनी विभिन्न जरूरतों के अनुरूप उत्पादों की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एड्रेनलिन रश के माध्यम से कंपनी प्रीमियम एनर्जी ड्रिंक खंड में अपनी मौजूदगी को और मजबूत कर रही है।कंपनी के अनुसार एड्रेनलिन रश 60 रुपये की कीमत पर उपलब्ध होगा। इसे दो वैरिएंट—'पैशन रश' और 'क्लासिक रश'—में पेश किया गया है। प्रीमियम कैन पैक में उपलब्ध इस उत्पाद में कैफीन, टॉरिन और विभिन्न विटामिन शामिल हैं। कंपनी का दावा है कि पैशन रश वैरिएंट बेहतर फोकस और क्लासिक रश वैरिएंट उच्च प्रदर्शन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

आईआईआरएफ-2026 रैंकिंग में बीबीएयू को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 19वां स्थान, विधि विभाग देश में 13वें स्थान पर

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) ने इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (आईआईआरएफ)-2026 में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों की श्रेणी में 19वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं विश्वविद्यालय के विधि विभाग ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर 13वीं रैंक हासिल की है। इस उपलब्धि को विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता, अनुसंधान उत्कृष्टता और विद्यार्थियों के समग्र विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण माना जा रहा है।इस सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने सभी शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश के अग्रणी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्थान प्राप्त करना संस्थान के लिए गौरव का विषय है। यह उपलब्धि शिक्षा, अनुसंधान और संस्थागत विकास के विभिन्न क्षेत्रों में विश्वविद्यालय के उत्कृष्ट प्रदर्शन को दर्शाती है तथा भविष्य में और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करती है।कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा, नवाचार और शोध के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में बीबीएयू राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान को और मजबूत करेगाआईआईआरएफ रैंकिंग में संस्थानों का मूल्यांकन विभिन्न मानकों के आधार पर किया जाता है। इनमें प्लेसमेंट प्रदर्शन, शिक्षण एवं अधिगम संसाधन, अनुसंधान की गुणवत्ता और प्रभाव, उद्योगों के साथ सहभागिता, करियर सहायता सेवाएं, भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयारी तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। इन सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के कारण बीबीएयू को यह सम्मानजनक स्थान प्राप्त हुआ है।वर्ष 1996 में स्थापित बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार उत्कृष्टता की दिशा में कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय के लखनऊ और अमेठी स्थित परिसरों में विभिन्न विषयों के स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इसके साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर एवं मेधावी विद्यार्थियों के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता योजनाएं भी संचालित की जाती हैं, जिससे समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को बढ़ावा मिलता है।

महिला से अभद्रता और अश्लील हरकत के आरोप में दो आरोपी गिरफ्तार

लखनऊ। माल थाना क्षेत्र में एक महिला एवं उसके परिजनों के साथ कथित रूप से अश्लील हरकत, गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार किए जाने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार थाना माल पर प्राप्त तहरीर में शिकायत की गई थी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा एक महिला तथा उसके परिजनों के साथ अशोभनीय व्यवहार करते हुए अश्लील हरकतें की गईं और गाली-गलौज की गई। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए थाना माल में मुकदमा अपराध संख्या 0122/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74 एवं 352 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है।

फर्जी बर्थडे बुकिंग कर वीडियोग्राफर से लाखों के उपकरण लूटे, 24 घंटे में तीन आरोपी गिरफ्तार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। इटौंजा थाना क्षेत्र में वीडियोग्राफर एवं उसके साथियों से लाखों रुपये मूल्य के फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी उपकरणों की लूट की घटना का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। स्वाट/सर्विलांस टीम (डीसीपी उत्तरी) और थाना इटौंजा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से लूटे गए कैमरे, लेन्स, गेम्बल, मोबाइल फोन, लाइट सेटअप, अवैध तमंचा तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है।पुलिस के अनुसार 2 जून 2026 को रानीखेड़ा, थाना माल निवासी अशोक यादव ने इटौंजा थाने में तहरीर देकर बताया था कि वह पेशे से वीडियोग्राफर हैं। उन्हें व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से जन्मदिन समारोह की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए बुकिंग मिली थी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जब वह अपने सहयोगियों के साथ ग्राम हीरापुरवा तिराहे से माल रोड की ओर जा रहे थे, तभी दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार बदमाशों ने उनकी कार रोक ली और तमंचे के बल पर छह कैमरे, सात लेन्स, दो गेम्बल, मोबाइल फोन तथा अन्य उपकरण लूटकर फरार हो गए।घटना के संबंध में थाना इटौंजा में मुकदमा दर्ज कर पुलिस उपायुक्त उत्तरी के निर्देशन में विशेष टीमों का गठन किया गया। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डाटा विश्लेषण, तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय सूचना तंत्र के आधार पर पुलिस ने तेजी से जांच आगे बढ़ाई।जांच के दौरान 3 जून को इटौंजा चौराहे के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल संख्या यूपी-32-सीएल-5465 पर सवार राम अनुज और विपिन मिश्रा उर्फ दुर्लभ मिश्रा को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान राम अनुज के कब्जे से एक देशी तमंचा और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए, जबकि विपिन के पास से एक मोबाइल फोन मिला। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि इसी मोबाइल का उपयोग फर्जी बर्थडे पार्टी बुकिंग कराने के लिए किया गया था।पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि वादी के साथ काम करने वाला सहयोगी रोहन कुमार शर्मा ही पूरे षड्यंत्र का मुख्य सूत्रधार था। उसने वादी की गतिविधियों, उपकरणों और कार्यक्रम की जानकारी अन्य आरोपियों को उपलब्ध कराई थी, जिसके आधार पर लूट की योजना बनाई गई। पुलिस ने रोहन कुमार शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने पहले से सुनियोजित तरीके से फर्जी कार्यक्रम तय किया और सुनसान स्थान पर पहुंचने के बाद तमंचे के बल पर वारदात को अंजाम दिया।

बालेन्द्र शाह ने सीमा विवाद सुलझाने के लिए ब्रिटेन को निमंत्रित कर अपनी जगहँसाई करवा ली है

भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को लेकर चल रहा पुराना सीमा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह कोई नया भू-राजनीतिक घटनाक्रम नहीं बल्कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की चौंकाने वाली और कई मायनों में अपरिपक्व बयानबाजी बनी है। संसद में उन्होंने ऐसा दावा कर दिया जिसने काठमांडू से लेकर नई दिल्ली तक हलचल मचा दी। हालात इतने असहज हो गए कि कुछ ही घंटों बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय को सफाई देने मैदान में उतरना पड़ा। और विडंबना देखिए, भारत को घेरने की कोशिश में दिया गया बयान नेपाल में ही प्रधानमंत्री के लिए भारी पड़ गया। विपक्ष, पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व राजदूत और सीमा विशेषज्ञ तक उनके खिलाफ खड़े हो गए और उनसे सबूत, स्पष्टीकरण, यहां तक कि माफी की मांग होने लगी। सीमा विवाद पर राजनीतिक परिपक्वता दिखाने के बजाय बालेन्द्र शाह की टिप्पणियां ऐसी साबित हुईं जिन्होंने नेपाल की आधिकारिक स्थिति को ही कठघरे में खड़ा कर दिया।

हम आपको बता दें कि नेपाली संसद में बोलते हुए बालेन्द्र शाह ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने के बाद पता चला कि केवल भारत ने ही नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई स्थानों पर भारतीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। उन्होंने दोनों देशों से तथ्यों का अध्ययन कर मित्रवत तरीके से विवाद सुलझाने की अपील की। उधर, नेपाल में विपक्षी दलों और पूर्व राजनयिकों ने बालेन्द्र शाह की टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। नेपाली कांग्रेस की बसना थापा और अन्य नेताओं ने संसद के अभिलेखों से बयान हटाने की मांग की। पूर्व विदेश मंत्री प्रदीप ज्ञवाली ने भी प्रधानमंत्री से माफी मांगने की बात कही। नेपाल के पूर्व राजदूत नीलाम्बर आचार्य और दीप कुमार उपाध्याय ने स्पष्ट कहा कि नेपाल द्वारा भारतीय भूमि पर अतिक्रमण का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। सीमा विशेषज्ञ बुद्धि नारायण श्रेष्ठ ने भी प्रधानमंत्री की बातों को तथ्यात्मक आधार से रहित बताया। इस प्रकार बालेन्द्र शाह का बयान भारत से अधिक नेपाल के भीतर ही विवाद का विषय बन गया। दरअसल, सीमा विवाद का केंद्र लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्र हैं। नेपाल का दावा है कि सुगौली संधि के अनुसार काली नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा से होता है, इसलिए उसके पूर्व का पूरा क्षेत्र नेपाली भूभाग है। दूसरी ओर भारत का कहना है कि काली नदी का वास्तविक उद्गम लिपुलेख दर्रे के नीचे स्थित स्रोतों से होता है और ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार कालापानी क्षेत्र लंबे समय से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा रहा है। यही मूल विवाद दोनों देशों के दावों की जड़ में है।

हम आपको बता दें कि विवाद को हाल में उस समय नया मोड़ मिला जब नेपाल ने लिपुलेख मार्ग से होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आपत्ति जताते हुए भारत और चीन दोनों को कूटनीतिक नोट भेजा। भारत ने इस आपत्ति को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि लिपुलेख मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा 1954 से लगातार संचालित हो रही है और यह कोई नया घटनाक्रम नहीं है। भारत ने यह भी दोहराया कि एकतरफा तरीके से क्षेत्रीय दावों का विस्तार न तो ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है और न ही स्वीकार्य है।

उधर, बालेन्द्र शाह के बयान पर विवाद खड़ा होने के बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री का आशय यह नहीं था कि नेपाल ने आधिकारिक रूप से भारतीय भूमि पर कब्जा किया है। मंत्रालय के अनुसार सीमा के कुछ हिस्सों में सीमा स्तंभों की कमी, दशगजा क्षेत्र और सीमापार भूमि उपयोग जैसी व्यावहारिक समस्याओं के कारण ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं जहां दोनों ओर के लोग एक-दूसरे की जमीन का उपयोग करते रहे हैं। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने यह भी दोहराया कि दोनों देश कूटनीतिक बातचीत, तकनीकी सर्वेक्षण और ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

लेकिन सबसे अधिक हैरानी प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के उस सुझाव पर हुई जिसमें उन्होंने सीमा विवाद के समाधान में ब्रिटेन की भागीदारी की बात उठाई। उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान सीमाओं की पृष्ठभूमि औपनिवेशिक काल से जुड़ी है, इसलिए ब्रिटेन को भी इस विषय में रुचि लेनी चाहिए। यह प्रस्ताव न केवल व्यावहारिक दृष्टि से कमजोर माना गया बल्कि नेपाल के भीतर भी इसे अपरिपक्व और अनावश्यक बताया गया। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद हमेशा द्विपक्षीय ढांचे में चर्चा का विषय रहा है। ऐसे में तीसरे पक्ष को बीच में लाने की बात कूटनीतिक परंपराओं और स्थापित समझ से मेल नहीं खाती। इसके अलावा, सीमा विवाद जैसे संवेदनशील और पूर्णतः द्विपक्षीय विषय में ब्रिटेन को शामिल करने का सुझाव बालेन्द्र शाह की कूटनीतिक नासमझी का ऐसा सार्वजनिक प्रदर्शन था जिसने कई जानकारों को हैरान कर दिया।

इंतजामों को अधिक सक्रिय करने की जरूरत

अनिरुद्ध गौड़

> भारत की बात करें तो सन 2010 में 31.3 मिलियन हेक्टर प्राकृतिक वन थे जो कि इसकी कुल भूमि का 11 फीसद था, लेकिन वर्ष 2023 में 134 किलो हेक्टेयर आद्र प्राकृतिक वन की हानि हो गई।

हमारे देश के वनों में गर्मियों के दिनों में आग लगना एक लगातार सिलसिला है। अप्रैल का महीना शुरू हुआ कि आग से जंगल धधकने लगते हैं। जंगल की आग पर्यावरण की दृष्टि से तो खतरनाक है ही जनजीवन और बायोडायर्वसटी की दृष्टि से भी हानिकारक है। ऐसे समय में जब जंगलों में आग लगती है तो देखा गया है कि उसकी तैयारी में सरकार विफल रही है।

देश के वनों में अप्रैल माह में आग की घटनाओं को देखें तो देश में हाल फिलहाल 361 जगह वनों में आग लगी हैं। इन घटनाओं की निगरानी को फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की साइट पर लांच बीटा संस्करण एसएनपीपी - वीआईआईआरएस का 10 अप्रैल, 2024 का भारत के वनों में लगी भीषण आग का मौजूद आंकड़ा बताता है कि सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में 122, तेलंगाना में 55, छत्तीसगढ़ में 47, उत्तराखंड में 32, बिहार में 23, ओडिसा में 22, उत्तर प्रदेश में 17 सहित 21 राज्यों में 361 जगह आग लगी थी जो 13 अप्रैल को घट कर काबू होने के बाद 33 रह गई। 1अप्रैल को देश के वनों में 132 बड़ी आग लगी थी जो 10 अप्रैल को 361 जगह तक पहुंच गई है। अप्रैल माह में पिछले 7 दिनों का आंकड़ा देखें तो एक्टिव आग की घटनाओं में टॉप फाइव राज्यों में छत्तीसगढ़ में 166, आंध्र प्रदेश में 248, मध्य प्रदेश में 207, ओडिसा में 146 और असम में 139 जगहों पर बड़ी आग लगी।

वहीं 1 नवम्बर, 2023 से 2024 में बड़ी आग की घटनाओं में टॉप फाइव राज्यों में आंध्र प्रदेश में 860, मध्य प्रदेश में 719, तेलंगाना 688, महाराष्ट्र में 547 और छत्तीसगढ़ में 527 बार आग लगी, जबकि वर्ष 2022-2023 में तो पूरे देश के वनों में 12562 आग की घटनाएं हुई। जंगल की आग से वनों का क्षरण तो होता ही है बहुमूल्य वन संपदा और कार्बन भी नष्ट हो जाते हैं। वनों का पारिस्थितिकी तंत्र भी प्रभावित होता है। यह देखा गया है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार जंगल की आग को मॉनिटर करने के लिए भारत में 2004 से शुरू सेटेलाइट की रिमोट सेंसिंग मोडिस अर्थात मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर सेंसर और 2017 से भारतीय सेटेलाइट से सम्पूर्ण भारत में एसएनपीपी-वीआईआईआरएस अर्थात सुओमी-नेशनल पोलर आर्बिटिंग पार्टनरशिप-विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट के साथ जीआईएस टूल्स की मदद से वनों की आग को मॉनिटर किया जा रहा है। देश का कुल 32,87,469 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र है।

नवीनतम आईएसएफआर 2021 के अनुसार देश का कुल 7,13,789 वर्ग किलोमीटर वन आवरण है। जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71 प्रतिशत है। वन सर्वे ऑफ इंडिया का अनुमान है कि देश में 36 प्रतिशत से अधिक वन क्षेत्र में बार-बार आग लगती रहती है। देश के करीब 4 प्रतिशत वन क्षेत्र में अधिक तो 6 प्रतिशत भाग में सबसे अधिक खतरा पाया गया है। ग्लोबल फॉरेस्ट वाच के अनुसार विश्व स्तर पर आग से वर्ष 2001 से 2022 के बीच 126 मिलियन हेक्टेयर वनों का नुकसान हुआ। इनमें वर्ष 2016 ऐसा वर्ष रहा जिसमें आग से सबसे अधिक 9.63 मिलियन हेक्टेयर वन आवरण का नुकसान हुआ। पिछले कुछ दशकों में आग की घटनाओं को देखें तो 2001 से 2022 के बीच भारत में आग की घटनाओं से 35.9 हेक्टेयर वृक्ष आवरण को नुकसान और 2.15 मेगा हेक्टेयर वृक्ष आवरण का नुकसान अन्य कारणों से हुआ। इसमें भी 2008 में आग से सबसे अधिक कुल 3.5 प्रतिशत वृक्ष आवरण का नुकसान हुआ।

अगर 12 अप्रैल 2021 से 8 अप्रैल 2024 के बीच आज की घटनाओं की बात की जाए तो 5,29,248 ड्डद्धद्धक्रस् के माध्यम से बड़ी आज की घटनाएं रिपोर्ट की गई है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व में हर वर्ष करीब 7 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र आग लगने की घटनाओं से प्रभावित होता है। इससे बड़े स्तर पर पर्यावरणीय और आर्थिक क्षति होती है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार विश्व में सन 2010 में 3.92 गीगा हेक्टेयर वृक्ष आवरण था जो पृथ्वी के 30 प्रतिशत से अधिक भू-भाग में फैला हुआ था, लेकिन 2023 में विभिन्न कारणों से 28.3 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष आवरण कम हो गया। सन 2001 से 2023 तक वैश्विक स्तर पर 488 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष आवरण की हानि हुई जो 2000 के बाद से वृक्ष आवरण में 12 प्रतिशत की कमी के बराबर है, जबकि सन 2002 से 2023 के बीच कुल 76.3 मिलियन हेक्टेयर आद्र प्राथमिक वन कम हो गया।

भारत की बात करें तो सन 2010 में 31.3 मिलियन हेक्टर प्राकृतिक वन थे जो कि इसकी कुल भूमि का 11 फीसद था, लेकिन वर्ष 2023 में 134 किलो हेक्टेयर आद्र प्राकृतिक वन की हानि हो गई। वर्ष 2002 से 2023 के बीच भारत में 414 हेक्टेयर आद्र प्राथमिक वन खो दिए। इस तरह भारत में कुल 4.1 प्रतिशत वन क्षेत्रफल कम हो गया। जिसमें 2016 और 2017 में अधिक हानि हुई। वनों में आग लगने से बड़े पैमाने पर मानवीय, पर्यावरण और आर्थिक हानि होती है। इसलिए आग फैलने से रोकना बहुत ही जरूरी है। वनों की आग को नियंत्रित करने में वही पुराने साधन और संसाधनों से आग काबू पाने के लिए राज्यों के महकमे लगे हुए हैं। तकनीक से हम बेहतर तरीके से मॉनिटर कर पा रहे हैं, लेकिन विकसित देशों की तरह वनों की आग को काबू पाने के इंतजामों को अधिक सक्रिय करने की जरूरत है।

टिप्पणी

शाह स्वच्छ छवि वाली सरकार भी नहीं दे पाए

रैपर से राजनेता बने बालेंद्र शाह ने अपने चंद दिनों के शासनकाल में नेपाल को अशांत कर दिया है। पूर्व सरकारों के खिलाफ भड़के असंतोष के कारण उल्का की तरह उगे शाह स्वच्छ छवि वाली सरकार भी नहीं दे पाए हैं।

बालेंद्र शाह को नेपाल का प्रधानमंत्री बने, अभी एक महीना नहीं हुआ है। लेकिन इसी बीच उनकी सरकार ने अलग- अलग जन समूहों में विरोध भड़का दिया है। वित्तीय गड़बड़ी के इल्जाम के कारण गृह मंत्री सुधन गुरुंग को इस्तीफा देना पड़ा। गुरुंग पिछले सितंबर में हुए हुए कथित जेन-जेड विद्रोह के प्रमुख संचालकों में थे। उनकी इसी भूमिका के कारण तजुर्बा ना होने के बावजूद उन्हें गृह मंत्रालय जैसा महत्त्वपूर्ण मंत्रालय मिला। मगर सिर्फ 26 दिन बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा। 27 मार्च को शपथ ग्रहण के बाद शाह सरकार से हटने वाले वे दूसरे मंत्री हैं। इसके पहले श्रम मंत्री दीपक शाह को भी वित्तीय गड़बड़ी के इल्जाम के कारण ही पद छोड़ना पड़ा था।

इस बीच शाह सरकार के कई फैसलों से नेपाल की सड़कों पर विरोध प्रदर्शनों की कड़ी लग गई है। शाह ने अपने आरंभिक कदमों में सियासी पार्टियों से जुड़े छात्र संघों को भंग कर दिया। इससे छात्र नाराज हो गए। फिर फैसला लिया कि भारत से 100 नेपाली रुपये से अधिक का सामान लाने पर सीमा शुल्क चुकाना होगा। इससे भारतीय सीमा से जुड़े मधेस इलाके में विरोध भड़क उठा। शाह ने जो कदम सबसे पहले उठाया, वह पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक की गिरफ्तारी था। मगर सरकार उनके खिलाफ साक्ष्य पेश नहीं कर पाई, जिस कारण कोर्ट ने दोनों को रिहा कर दिया।

इससे ओली समर्थकों को सड़कों पर उतरने का मौका मिला। फिर शाह ने सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों, मंत्रियों, राष्ट्रपतियों और यहां तक कि पूर्व राजा की संपत्ति की जांच कराने का फैसला भी किया है। इससे आरोप लगा है कि बुनियादी समस्याओं का हल तलाशने के बजाय शाह बदले की भावना से काम कर रहे हैं। तो कुल मिला कर रैपर से राजनेता बने शाह ने अपने चंद दिनों के शासनकाल में नेपाल को अशांत एवं अस्थिर कर रखा है। पूर्व सरकारों की अकुशलता, कथित भ्रष्टाचार, और भाई-भतीजावाद से भड़के असंतोष के कारण उल्का की तरह उगे शाह स्वच्छ छवि वाली सरकार भी नहीं दे पाए। नतीजा, तेजी से उनकी चमक का उड़ जाना है।

ब्लॉग

पंजाब त्रिस्तरीय निकाय चुनाव के दलगत, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सियासी मायने अहम

कमलेश पांडे

पंजाब के त्रिस्तरीय शहरी निकाय चुनाव- नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत- सिर्फ स्थानीय सत्ता का संघर्ष नहीं हैं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव का "सेमीफाइनल" माने जा रहे हैं। ये चुनाव सिर्फ स्थानीय प्रशासनिक चुनाव नहीं हैं, बल्कि ये पंजाब की बदलती क्षेत्रीय राजनीति, राष्ट्रीय दलों की रणनीति और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की संघीय लोकतांत्रिक छवि से भी जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि 2026 के इन चुनावों को 2027 विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा "पॉलिटिकल टेस्ट" माना जा रहा है।

पंजाब नगर निकाय चुनाव 2026 के चुनाव आयोग और मतगणना से जुड़े अब तक के मुख्य आंकड़े निम्नलिखित हैं- कुल 102 शहरी निकायों- नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों- में चुनाव हुए, जहां मतदान प्रतिशत लगभग 63.94% दर्ज किया गया। नगर पंचायतों में सबसे अधिक 76.18% मतदान हुआ। नगर निगम क्षेत्रों में सबसे कम लगभग 59.91% मतदान दर्ज हुआ। नगर परिषदों में लगभग 65.06% मतदान हुआ। कुल 1,896 वार्डों के लिए मतदान कराया गया। लगभग 7,555 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से 79 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए।

इस चुनाव में अब तक आए नतीजों और घोषित रुझानों के अनुसार आम आदमी पार्टी ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी बनी है। आप ने लगभग 886 वार्ड जीते। जबकि कांग्रेस ने लगभग 358 वार्ड जीते। वहीं शिरोमणि अकाली दल (SAD) को 191–192 वार्ड, भाजपा को 172 वार्ड, बसपा को 7 वार्ड, और निर्दलीय उम्मीदवारों को 251 वार्ड पर जीत मिली। वहीं सीट प्रतिशत के हिसाब से मोटे अनुमान के मुताबिक, आप ने लगभग 50% के आसपास वार्ड, कांग्रेस ने लगभग 20% वार्ड, एसएडी ने लगभग 9% वार्ड, बीजेपी ने लगभग 7% वार्ड और बीएसपी सहित अन्य ने लगभग 14% सीटो पर जीत व बढ़त हासिल की है।

जहाँ तक वोट प्रतिशत का सवाल है, तो विभिन्न मीडिया रिपोर्टों और संकलित रुझानों के अनुसार दल और अनुमानित वोट प्रतिशत इसप्रकार हैं- आम आदमी पार्टी को लगभग 41–44%, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लगभग 24–27%, भारतीय जनता पार्टी को लगभग 13–16%, शिरोमणि अकाली दल को लगभग 10–13% और निर्दलीय व अन्य लगभग 5–8% वोट हासिल हुए हैं। इस प्रकार आप का वोट शेयर सबसे अधिक रहा, जबकि कांग्रेस दूसरे नंबर पर, शिरोमणि अकाली दल तीसरे नम्बर पर रही और इसने ग्रामीण-सिख बेल्ट में कुछ आधार वापस पाया, जबकि बीजेपी चौथे स्थान पर जाकर कुछ शहरी पॉकेट्स तक सीमित रही। आधिकारिक वोट प्रतिशत का सबसे विश्वसनीय डेटा sec.punjab.gov.in पर उपलब्ध है।

अब जिस तरह से इन चुनावों के नतीजे आए हैं, उसने यह तय कर दिया है कि राज्य की राजनीति में आम आदमी पार्टी की जमीन मजबूत हो रही है और कांग्रेस, भाजपा, एसएडी जैसे विपक्षी दल बचाव की मुद्रा में आ चुके हैं। लिहाजा पंजाब त्रिस्तरीय शहरी निकाय चुनाव के दलगत, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सियासी मायने अहम हैं।

पहला, आप (AAP) अपने जनविश्वास की परीक्षा में सफलः मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के लिए यह चुनाव सत्ता में आने के बाद शहरी जनसमर्थन मापने का अवसर था, जो बड़ी जीत के साथ उम्मीदों पर खरा उतरा। निकायों में मजबूत जीत मिली है। इससे यह संदेश गया कि पंजाब में आप सिर्फ "वैकल्पिक प्रयोग" नहीं, बल्कि स्थायी राजनीतिक शक्ति बन चुकी है। आप की बड़ी जीत इसी ओर संकेत करती है। आप (AAP) के लिए ये चुनाव सबसे अहम थे क्योंकि वह राज्य की सत्ता में है। नगर निकायों में मजबूत प्रदर्शन से यह संदेश गया कि जनता अभी भी मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार पर भरोसा कर रही है। इसमें आप के लिए फायदे की बात यह है कि शहरी वोट बैंक पर पकड़ मजबूत होने से "दिल्ली मॉडल" की तरह ₹पंजाब मॉडल₹ को भी प्रचारित करने का अवसर मिला। साथ ही विपक्ष के बिखराव का भी लाभ मिला। वहीं, आप के लिए खतरे की बात यह है कि नशा, कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक दखल के आरोप बड़ी चुनौती बने हुए हैं।

दूसरा, कांग्रेस के अस्तित्व की लड़ाई पर विपक्षी हैसियत बनाईः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए पंजाब आखिरी बड़े राज्यों में से एक है जहाँ वह अब भी राजनीतिक पुनर्जीवन की उम्मीद देखती है। वह मिली भी और पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी की हैसियत पा गई। भले ही कांग्रेस ने निकाय चुनावों में कमजोर प्रदर्शन किया, लेकिन इतनी सीट मिल गई कि उसका संगठनात्मक संकट ज्यादा नहीं बढ़ेगा। पंजाब कभी कांग्रेस का मजबूत गढ़ था, लेकिन लगातार संगठनात्मक कमजोरी और गुटबाजी ने उसे कमजोर किया है। फिर भी कांग्रेस के लिए अवसर यह है कि कई शहरों में दूसरे स्थान पर भी उसने मजबूत उपस्थिति दिखाई है, और वह खुद को मुख्य विपक्ष के रूप में स्थापित कर चुकी है, जबकि आगे शहरी असंतोष को भुनाने का मौका मिलेगा।

तीसरा, अकाली दल के पुनर्जीवन का संघर्ष बढ़ाः शिरोमणि अकाली दल किसान आंदोलन और पुराने सत्ता-विरोधी माहौल के बाद अपनी खोई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन चुनावों ने बता दिया कि "पंजाबियत" और क्षेत्रीय पहचान की राजनीति अभी कितनी प्रभावी है। शिरोमणि अकाली दल के लिए ये चुनाव "राजनीतिक पुनर्जीवन" की परीक्षा थे और आगे भी रहेंगे। किसान आंदोलन और पुराने भ्रष्टाचार आरोपों के बाद पार्टी जो कमजोर हुई थी, वह स्थिति नहीं बदली है।

लिहाजा अब वह खुद को "पंजाबियत" और क्षेत्रीय अस्मिता की पार्टी के रूप में फिर स्थापित करना चाहती है। शिरोमणि अकाली दल के लिए सकारात्मक संकेत यह है कि ग्रामीण-सिख वोट बैंक में आंशिक वापसी हुई, जो भाजपा से अलग होकर स्वतंत्र पहचान मजबूत करने की कोशिश हो सकती है, जबकि उसकी चुनौती यह है कि शहरी क्षेत्रों में कमजोर संगठन के चलते युवा मतदाताओं के बीच सीमित आकर्षण है।

चौथा, भाजपा के विस्तार की प्रयोगशालाः भारतीय जनता पार्टी पंजाब में शहरी हिंदू वोट और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों के सहारे धीरे-धीरे विस्तार करना चाहती है। इसमें वह सफल रही। भाजपा नगर निकायों में सीटें ज्यादा नहीं बढ़ा पाई है, लिहाजा वह 2027 में गठबंधन राजनीति के बिना भी अधिक आक्रामक रणनीति अपना सकती है। भाजपा के लिए पंजाब अभी भी विस्तार का राज्य है। पार्टी हिंदू-शहरी वोट और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों के सहारे जगह बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि यहां भाजपा के लिए अवसर यह है कि कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल की कमजोरी का लाभ मिलेगा और शहरी निकायों में सीटें बढ़ाकर दीर्घकालिक आधार तैयार करने में सहूलियत होगी। हालांकि सबसे बड़ी बाधा किसान आंदोलन के बाद ग्रामीण पंजाब में अविश्वास। के चलते राज्य में अभी भी सीमित संगठनात्मक नेटवर्क है।

पांचवां, पंजाब में बहुजन समाज पार्टी (BSP) अकेले चुनाव लड़कर दलित वोट बैंक को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है, जो इस बार भी नहीं मिली। क्योंकि वहां बड़ी दलित आबादी होने के कारण बीएसपी भविष्य की राजनीति में "किंगमेकर" की भूमिका देख रही है। लिहाजा इन चुनावों से उभरते बड़े संकेत इस बात की तस्दीक करते हैं कि पंजाब की राजनीति अब पूरी तरह बहुकोणीय हो चुकी है। शहरी मतदाता विकास के साथ-साथ नशे और प्रशासनिक जवाबदेही को भी अहम मुद्दा मान रहा है।

पंजाब के त्रिस्तरीय निकाय चुनावों ने तीन बड़े संकेत दिए हैं जिनके क्षेत्रीय मायने स्पष्ट हैं- पहला, पंजाब की राजनीति अब स्थायी रूप से बहुकोणीय हो चुकी है। दूसरा, 'आप' फिलहाल मजबूत हुई है, लेकिन विपक्ष समाप्त नहीं हुआ। तीसरा, पंजाब की राजनीति अब केवल स्थानीय मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विपक्ष, संघीय लोकतंत्र और अंतरराष्ट्रीय प्रवासी राजनीति से भी जुड़ चुकी है, जिसके क्षेत्रीय फायदे भी दिखेंगे।

चौथा, इन चुनावों से ऐसा प्रतीत हुआ है कि स्थानीय मुद्दों पर क्षेत्रीय जनमत हावी है। यही वजह है कि इस बार सिर्फ सड़क, पानी और सफाई ही नहीं, बल्कि बेरोजगारी, नशा, कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार भी बड़ा मुद्दा बने। कई जगह मतदाताओं ने जवाबदेही की मांग की। पांचवां, बहुकोणीय मुकाबले ने राजनीति बदली है। लिहाजा, आप, कांग्रेस, भाजपा, शिरोमणि अकाली दल (SAD) और बहुजन समाज पार्टी (BSP)— सभी के लिए अलग-अलग सियासी स्पेस बनते प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि सभी दलों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दिए थे। इन चुनावों से पंजाब में "दो-दलीय राजनीति" की बजाय बहुकोणीय राजनीति और मजबूत हुई है।

दिलचस्प बात तो यह है कि आप फिलहाल भारी बढ़त में दिखी है, लेकिन विपक्ष पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। लिहाजा 2027 विधानसभा चुनाव में गठबंधन राजनीति और सीट-समझौते फिर अहम हो सकते हैं। कुल मिलाकर, ये चुनाव सिर्फ मेयर या पार्षद चुनने के नहीं, बल्कि पंजाब की अगली राजनीतिक दिशा तय करने वाले चुनाव बन चुके हैं। लिहाजा, इन चुनावों के राजनीतिक मायने बड़े हैं, क्योंकि ये 2027 विधानसभा चुनाव का ट्रेलर समझे जा रहे हैं। इन चुनावों को पंजाब की जनता का "मूड टेस्ट" माना जा रहा है। वहीं, शहरी क्षेत्रों में किस दल की पकड़ मजबूत है, इससे अगले विधानसभा चुनाव की रणनीति तय होगी।

पहला, 2029 लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमिः पंजाब के ये चुनाव राष्ट्रीय दलों के लिए "मूड इंडिकेटर" हैं। 2029 लोकसभा चुनाव से पहले यह देखा जा रहा है कि क्षेत्रीय दल आप यहां निरंतर मजबूत हो रही है और राष्ट्रीय दलों का प्रभाव कम हो रहा है।

दूसरा, विपक्षी राजनीति का संकेतः चूंकि कांग्रेस और आप दोनों पंजाब में प्रतिस्पर्धा जारी है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता की संभावनाएँ कमजोर प्रतीत होती हैं और कांग्रेस/भाजपा विरोधी तीसरे मोर्चे को पंख लग सकते हैं। इससे भाजपा को विपक्ष के बिखराव का लाभ मिल सकता है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष की राजनीति में आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का दबदबा बढ़ेगा, वह भाजपा के लिए भावी चिंता का सबब बन सकती है।

तीसरा, संघीय राजनीति का मॉडलः पंजाब में बहुकोणीय मुकाबला दिखाता है कि भारत की राजनीति अब पूरी तरह द्विध्रुवीय नहीं रही। यहाँ क्षेत्रीय अस्मिता, किसान राजनीति, धर्म, युवा रोजगार और शहरी प्रशासन—सब मिलकर चुनावी समीकरण तय किए, जिससे सत्ताधारी आप को बहुत फ़ायदा मिला।

चौथा, लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयताः चुनावों के दौरान प्रशासनिक दखल, बूथ प्रबंधन और निष्पक्षता को लेकर आरोप भी लगे। विपक्ष ने राज्य मशीनरी के दुरुपयोग की शिकायतें उठाईं। ऐसे मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव आयोग और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर बहस को बढ़ाते हैं। लेकिन यह बेतुकी बात है और विपक्षी सियासी हथकंडे के अलावा कुछ नहीं है।

यूपी में चार कत्ल: 'बंटी-बबली, बहू ने मारा', शवों के पास गत्ते पर लिखा था

आर्यावर्त संवाददाता

प्रयागराज। प्रयागराज के साउथ मलाका स्थित बंद मकान में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या के मामले में जांच के दौरान नया मोड़ सामने आया है। पुलिस को घटनास्थल के पास एक गत्ता रखा मिला जिस पर लिखा था, ₹बंटी बबली बहू ने मारा है।₹ इस सुराग के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। लिखावट का मिलान कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ताकि पता लगाया जा सके कि यह किसने लिखा था। जांच में यह भी सामने आया कि मृतक वीरेंद्र कुमार वैश्य के छोटे बेटे अश्विनी ने करीब 15 वर्ष पहले रितु यादव नाम की युवती से प्रेम विवाह किया था। अश्विनी और रितु वर्ष 2024 में धोखाधड़ी के एक मामले में कौशांबी जेल भी जा चुके हैं। उन पर मेट्रिमोनियल साइट के जरिये लोगों से ठगी करने का आरोप लगा था।

स्थानीय स्तर पर दोनों को बंटी-बबली नाम से जाना जाता था। पुलिस

इलाके की दिनचर्या में कोई बदलाव या संदिग्ध गतिविधि का भी पता लगाया जा रहा

पुलिस हर गतिविधि को क्रमवार जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसके लिए स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। इनमें दूध देने वाले, अखबार वाले और आसपास के दुकानदार शामिल हैं। उस दिन इलाके की दिनचर्या में कोई बदलाव या संदिग्ध गतिविधि का पता लगाया जा रहा है। एसीपी कोतवाली रवि गुप्ता ने बताया कि जल्द ही अहम सुराग मिलने की उम्मीद है।

सूत्रों के अनुसार, पारिवारिक संबंधों में लंबे समय से तनाव था। करीब 15 महीने पहले वीरेंद्र कुमार वैश्य ने अपने छोटे बेटे अश्विनी को संपत्ति से बेदखल कर दिया था। ऐसे में पुलिस संपत्ति विवाद, पारिवारिक रंजिश और घटनास्थल से मिले संदेश को जोड़कर जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही हत्या के कारणों की स्थिति सामने आएगी। मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला कि अश्विनी और रितु के खिलाफ मंझनपुर और पश्चिमशरीरा कोतवाली में एफआईआर दर्ज हैं। अश्विनी और रितु ने प्रतिष्ठित मेट्रिमोनियल वेबसाइटों पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाया। फिर करोड़ों रुपये की ठगी की। दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। वर्ष 2024 में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल अश्विनी कौशाम्बी जेल में बंद है, जबकि पत्नी का पता नहीं चल सका है।

एक ही परिवार के चार लोगों की सिर कुंचकर हत्या की गई है। मामले में संपत्ति विवाद से लेकर अन्य कई पहलुओं पर जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

डॉ. अजय पाल शर्मा अपर पुलिस आयुक्त

जांच की दिशा मोड़ने की साजिश तो नहीं

बंटी-बबली बहू ने मारा... पुलिस को आशंका है कि यह सुराग कहीं जांच की दिशा भटकाने के लिए तो नहीं छोड़ा गया। जांच से जुड़े सूत्रों का कहना है कि यह भी संभव है कि हत्यारों ने जानबूझकर किसी व्यक्ति या परिवार को संदेह के घेरे में लाने के लिए यह खेल किया हो। कई आपराधिक मामलों में अपराधी पुलिस को भ्रमित करने और जांच की दिशा बदलने के लिए ऐसे सुराग छोड़ते रहे हैं। इसी आशंका को देखते हुए पुलिस और फोरेंसिक टीम गत्ते पर लिखी राइटिंग, फिंगरप्रिंट और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों की जांच कर रही है।

वीरेंद्र के घर के पास लगे हैं सात कैमरे

वीरेंद्र के घर के आसपास ट्रैफिक पुलिस के सात कैमरे लगे हैं। इनमें से दो कैमरों का झुकाव सीधे घर की ओर है। इन दो कैमरों में से एक कैमरा चारों दिशाओं में घूमने (360 डिग्री) की क्षमता वाला है, जिससे आसपास की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। चार कैमरे उस खंभे पर हैं जो उनके घर के सबसे नजदीक हैं। यानी नजदीकी पॉइंट पर निगरानी ज्यादा मजबूत है।

करीबी और रिश्तेदार भी संदेह के घेरे में

कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि वारदात में किसी जान-पहचान वाले या करीबी की भूमिका तो नहीं है। इसी कारण रिश्तेदारों और उनके संपर्कों की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस दुकान के किरायेदारों से भी पूछताछ कर रही है।

बेची गई थीं तीन दुकानें

जांच कई नए एंगल से आगे बढ़ रही है। सामने आया कि परिवार ने तीन दुकानों को बेच दिया है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन दुकानों की बिक्री के पीछे क्या वजह थी? क्या इसका किसी तरह का संबंध इस वारदात से हो सकता है? हालांकि पुलिस ने इस पहलू पर कोई आधिकारिक निष्कर्ष नहीं दिया है। पुलिस मानकर चल रही कि वारदात के पीछे केवल हत्या नहीं, बल्कि लूट की मंशा भी हो सकती है।

कारोबारी, उनकी पत्नी, बेटा व बेटी की सिर कूंचकर हत्या, बंद घर में मिले शव

प्रयागराज शहर के बीचों-बीच साउथ मलाका के सब्जी मंडी चौराहा स्थित मकान में कारोबारी, उनकी पत्नी, बेटा और बेटी की सिर कुंचकर हत्या कर दी गई। मंगलवार को दुर्गंध आने पर घर का ताला तोड़ा गया तो कारोबारी वीरेंद्र कुमार वैश्य (70), पत्नी अनीता (65), बेटी मीनाक्षी (45) और बेटे अभिषेक (40) के शव अलग-अलग कमरे में खून से लथपथ पड़े मिले। चारों के सिर पर गहरी चोट के निशान थे। शुरुआती जांच में करोड़ों रुपये की संपत्ति के लालच में वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई गई है। वीरेंद्र कुमार वैश्य साउथ मलाका चौराहा स्थित अपने घर में पत्नी, बेटी और बड़े बेटे के साथ रहते थे। छोटे बेटे अश्विनी को उन्होंने करीब 15 साल पहले संपत्ति से बेदखल कर दिया था।

करीब 200 वर्ग गज के इस मकान के भूतल में 14 दुकानें हैं। इनमें 12 किरायेदार हैं। उक्त दुकानों से हर महीने एक लाख रुपये से अधिक का किराया आता है। एक दुकान अभिषेक की है। दूसरी बेटी मीनाक्षी की है। मीनाक्षी ने हाल ही में गिफ्ट गैलरी के नाम से काम शुरू किया था। इस दुकान पर बेटी के साथ वीरेंद्र भी बैठते थे। वीरेंद्र की पत्नी अनीता बीमारी की वजह से पहली मंजिल पर बने कमरे में रहती थीं।

मंगलवार दोपहर करीब तीन बजे पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी कि मकान से तेज दुर्गंध आ रही है। कोतवाली पुलिस पहुंची तो घर में ताला जड़ा हुआ था। ताला तोड़कर पुलिस ऊपर कमरे में पहुंची तो वीरेंद्र और उनकी पत्नी के शव बेड पर पड़े थे। खोजबीन के दौरान बगल वाले कमरे में बेटी का शव फर्श पर पड़ा मिला। उसके सिर पर गहरे चोट के निशान थे। पुलिस ने भारी वस्तु से हमला करने की आशंका जताई है। तीनों के शव मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई।

दोहरा कारखाना पर छापा, दो भाई गिरफ्तार

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। नगर कोतवाली पुलिस ने अवैध रूप से दोहरा के निर्माण और कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से करीब दो कुंतल अवैध दोहरा बरामद किया है। बरामद माल का नमूना जांच के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग को भेज दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर नगर आयुष श्रीवास्तव ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक त्रिवेणी सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर शकरमंडी मोहल्ले में एक बर्तन के दुकान में छापेमारी की।छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से अवैध दोहरा का निर्माण और बिक्री कर रहे दो सगे भाइयों पवन साहू और विवेक साहू को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बड़ी मस्जिद के निवासी बताए गए हैं। तलाशी के दौरान

पुलिस ने उनके पास से लगभग दो कुंतल अवैध दोहरा बरामद किया।पुलिस के अनुसार बरामद दोहरा का निर्माण बिना वैध अनुमति और निर्धारित मानकों के विपरीत किया जा रहा था। आशंका है कि यह सामग्री शहर और आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई की जा रही थी। कार्रवाई के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। खाद्य सुरक्षा विभाग को भी मामले की सूचना दी गई है। बरामद दोहरा का नमूना जांच के लिए भेजा गया है, ताकि इसकी गुणवत्ता और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच की जा सके। जांच रिपोर्ट आने के बाद आरोपियों पर अन्य धाराएं भी बढ़ाई जा सकती हैं।

निर्माणाधीन जिला कारागार का डीएम ने किया निरीक्षण

जौनपुर। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. द्वारा निर्माणाधीन नवीन जिला कारागार के निर्माण कार्य का निरीक्षण कर निर्माण प्रगति की जानकारी प्राप्त की गई। जिलाधिकारी ने कार्यों की गुणवत्ता एवं उपलब्ध संसाधनों की विस्तृत समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि श्रमिकों की संख्या, आवश्यक मशीनों और सामग्रियों की उपलब्धता बढ़ाकर निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए, जिससे निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य पूर्ण कराया जा सके। उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि निर्माणाधीन ड्रेनेज सिस्टम को इस प्रकार बनाया जाए कि वर्षा के दौरान कहीं भी जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो। समस्त आवासीय एवं अनावासीय परिसरों से जल निकासी व्यवस्था सुचारू रूप से सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही मल्टीपरपज हॉल एवं हाई सिक्योरिटी बैरक के कार्य को भी शीघ्र पूर्ण करने तथा मिट्टी को समतल कर उसे बगीचे के रूप में विकसित किए जाने के भी निर्देश दिए।

काशी में आधी रात को चला बुलडोजर, जानें क्यों ढहाई गई 200 साल पुरानी अजगैब शहीद मस्जिद?

आर्यावर्त संवाददाता

वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विकास और विस्तारीकरण योजना को लेकर एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। काशी रेलवे स्टेशन को आधुनिक रूप देने और मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाने के उद्देश्य से चल रहे काम के बीच आ रही करीब दो सौ साल पुरानी अजगैब शहीद मस्जिद को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, यह मस्जिद रेलवे की जमीन पर बनी थी और स्टेशन के विस्तारीकरण की जद में आ रही थी।

इस पूरी कार्रवाई को बेहद गोपनीय और रणनीतिक तरीके से अंजाम दिया गया। सोमवार रात करीब 11।15 बजे भारी सुरक्षा बल के साथ अधिकारी मौके पर पहुंचे और रात 12।15 बजे तक, यानी महज एक घंटे के भीतर मस्जिद को ध्वस्त कर वहां से मलबा भी हटा दिया गया।

कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से

निपटाने के लिए मौके पर जॉइंट सीपी शिव हरि मीणा के नेतृत्व में आधा दर्जन आईपीएस अधिकारी, सैकड़ों पुलिसकर्मी और पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान तैनात थे। सुरक्षा के मद्देनजर मीडिया समेत किसी भी बाहरी व्यक्ति को परिसर के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। इस दौरान पांच जेसीबी और दो पोकलैंड मशीनों की मदद से ढांचा ढहाया गया।

अफसरों ने खुद संभाली कमान

ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होने से पहले जेसीपी शिवहरी मीणा ने आला अफसरों के साथ मिलकर पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया था। मौके पर डीसीपी काशी गौरव बंसवाल, एडीसीपी वैभव बांगर, एसीपी विजय प्रताप और कोतवाली व चेतगंज के एसीपी समेत कई थानों की फोर्स तैनात रही ताकि कानून-व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े। फिलहाल इस कार्रवाई पर मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

कैसा होगा नया मल्टी-मॉडल हब?

दरअसल, वाराणसी के काशी रेलवे स्टेशन को लगभग 330-400 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं वाले मल्टी-मॉडल हब या इंटर मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य ट्रेन, बस, मेट्रो और जल परिवहन (वाटर ट्रांसपोर्ट) को एक ही छत के नीचे जोड़ना है, जिससे यात्रियों को सुगम यातायात मिल सके। इसी भव्य प्रोजेक्ट को रफ्तार देने के लिए इस अतिक्रमण हटाओ अभियान को अंजाम दिया गया है।

18 ग्राम पंचायतों में प्रशासक हुए नियुक्त

जौनपुर। जिले की 18 ग्राम पंचायतों में अब सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) प्रशासक की भूमिका निभाएंगे। इन अधिकारियों को इन पंचायतों के विकास कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह निर्णय ग्राम पंचायतों के अस्थाई संचालन को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। शासन के निर्देशानुसार, 26 मई को कार्यकाल पूरा होने के बाद अधिकांश ग्राम पंचायतों में संबंधित ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त किया गया है। हालांकि, वे नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते। लेकिन, जौनपुर की इन 18 ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों की जगह समितियां कार्यरत थीं। इन पंचायतों में कुछ प्रधानों का निधन हो चुका है, जबकि कुछ के खिलाफ अनियमितता के आरोप हैं। इस स्थिति को देखते हुए, इन ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को सुचारु रूप से जारी रखने के लिए सहायक विकास अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त किया गया है।

जमीन में एक-एक कर समाई दर्जनों गाड़ियां, बारिश के बाद का खौफनाक मंजर

आर्यावर्त संवाददाता

आगरा। मुख्यमंत्री के नाम पर सड़कों के विकास के लिए शुरू की गई सीएम ग्रिड योजना के निर्माण कार्य एक ही बारिश में बह गए। बसई मंडी से इंद्रापुरम और इंद्रापुरम से अमर होटल तक सीएम ग्रिड की निर्माणाधीन सड़कें के बारिश में धंसने से 12 कारें और वैन पलट गईं। तीन से चार फीट तक धंसीं सड़कों के गड्ढों में वाहन फंस गए, जिन्हें शाम तक हाइड्रा मशीन मंगाकर निकलवाया गया। गड्ढों में वाहन गिरने से कई लोग घायल हो गए। बारिश के कारण नाले उफनाने से सड़कों पर दो फीट तक जलभराव हो गया।

सीएम ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (सीएम ग्रिड) योजना के तहत नगर निगम ने काम शुरू कराया है। बसई रोड से इंद्रापुरम रोड तक के हिस्से में 10 फीट गहराई पर यूटिलिटी डक्ट, सीवर और पानी की लाइनें बिछाई गई हैं। लाइनें बिछाकर मिट्टी और गिट्टी बिछा दी गई। पार्षद दीपक

वर्मा ने बताया कि सोमवार रात की बारिश में सड़क पानी से लबालब हो गई। सुबह कार चालक यहां से निकले तो वह पानी भरा देखकर गड्ढों को भांप नहीं सके और इनमें फंसते चले गए। करीब 12 कारें और वैन इन गड्ढों में फंसने के बाद पलट गईं। गनीमत रही कि चालक बाल-बाल बच गए। उन्हें क्षेत्रीय लोगों ने जैसे-तैसे बाहर निकाला। पूरी सड़क दलदल में तब्दील हो गई। दलदल में बदल गई सड़क पर टोरंट की मरम्मत वैन और कचरा उठाने वाली गाड़ियां भी फंस गईं। टोरंट पावर की टीम इंद्रापुरम में फॉल्ट ठीक करने के लिए जा रही थी। अचानक चारों पहिये धंस गए। वैगन-आर कार यहां गड्ढों में फंसकर पलट गई। इसमें सवार तीन लोगों को क्षेत्रीय लोगों ने बाहर निकाला, उन्हें मामूली चोट आई।

नगर आयुक्त ने देखी सड़कों की दुर्दशा

नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने ताजगंज क्षेत्र में सीएम ग्रिड के काम की दुर्दशा देखी। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण सीएम ग्रिड के विकास कार्य प्रभावित हुए हैं, उनकी प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कराई जाएगी। जिन स्थानों पर सड़क धंसने से गड्ढे बन गए हैं, उन्हें तत्काल भरकर यातायात के लिए सुरक्षित बनाया जाए। इस दौरान चीफ इंजीनियर अरविंद श्रीवास्तव और अवर अभियंता कृष्ण गोपाल मौजूद रहे।

ताज से किले के बीच पांच जगह धंसी सीवर लाइन, थम गया ट्रैफिक

ताजमहल के पास पुरानी मंडी से शाहजहां पार्क के बीच नमामि गंगे योजना के तहत बिछाई गई सीवर लाइन वाला हिस्सा बारिश के बाद धंस गया। पुरानी मंडी से किले के बीच पांच जगह 15 फीट तक चौड़े और 4 से 8 फीट गहरे गड्ढे हो गए। इससे रोड पर वाहनों का आवागमन रोक दिया गया। ताजगंज निवासी राजेश राठौर ने सुबह सड़क जगह-जगह धंसी देखी तो बैरिकेडिंग लगाकर वाहन चालकों को सतर्क किया। जलनिगम के नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर आरपी सिंह ने बताया कि बारिश के कारण सीवर लाइन वाले हिस्से में मिट्टी धंसी है। ठेकेदार को सड़क की मरम्मत और बैरिकेडिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं।

आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर-4 में पुलिस चौकी के पास सीवर लाइन लीक होने से गहरा गड्ढा हो गया। इसमें सोमवार को पुलिस चौकी पर सीज करके लाई गई 7000 ईंटों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली सड़क धंसने से समा गई। मंगलवार दोपहर में मशीन मंगवाकर ट्रैक्टर-ट्रॉली को निकलवाया गया। रात में बारिश और सीवर लीकेज के कारण गड्ढे में पानी भर गया। ईंटें गिरने से पीएनजी और पानी की 18 इंच की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इससे आवास विकास कॉलोनी में पानी का संकट बना रहा। सोमवार रात को टूटी पानी की लाइन की मरम्मत का काम मंगलवार शाम को ट्रैक्टर-ट्रॉली निकालने के बाद शुरू कराया गया। जलकल विभाग के कार्यवाहक महाप्रबंधक संघभूषण ने बताया कि गड्ढे में भरे पानी को निकलवाया गया। 18 इंच पाइप लाइन से पूरे आवास विकास को आपूर्ति की जाती है। देर रात तक मरम्मत कार्य पूरा होने के आसार हैं। वहीं लीकेज सीवर लाइन का काम वीए टेक वबाग को सौंपा गया है। कंपनी जांच के बाद यहां करीब 70-80 मीटर हिस्से में सीवर लाइन बदलेगी। पीएनजी लाइन भी ठीक करा दी गई।

इतनी रही लागत

42.78 करोड़ से बनाई जा रही बसई मंडी से इंद्रापुरम चौराहे तक की सड़क

47.43 करोड़ से बन रही इंद्रापुरम चौराहे से अमर होटल तक की सड़क

90 दिन पहले शुरू हुआ था निर्माण

2.50 लाख लोग व्यवस्थित ढंग से निर्माण न होने के कारण परेशान

अनीता सिंह का शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में स्थान

जौनपुर। कुमायूँ विश्वविद्यालय की भीमताल परिसर, नैनीताल स्थित तकनीकी संकाय की संकायाध्यक्ष प्रोफेसर अनीता सिंह को साइंस रैंक ग्लोबल द्वारा जारी सूची में विश्व के शीर्ष 05 प्रतिशत वैज्ञानिकों में स्थान प्राप्त हुआ है। यह सूची वैज्ञानिकों द्वारा किये जा रहे उत्कृष्ट शोध कार्यों, उच्च गुणवत्ता वाले शोध प्रकाशनों तथा वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय में दिये गये महत्वपूर्ण योगदान के आधार पर तैयार की जाती है। इस सूची में स्थान बनाने वाली अनीता सिंह अपने पिता स्व० श्री प्रेम नारायण सिंह, रीडर, भौतिक विज्ञान, तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लाइन बाजार जौनपुर में परिवार सहित निवास करती थीं। इनका विवाह कैप्टन दिनेश कुमार सिंह, निवासी ग्राम नदवा बिशुनपुर, थाना चैराखास, जनपद कुशीनगर से हुआ। वर्तमान में भीमताल, जनपद नैनीताल, उत्तराखण्ड में परिवार सहित निवास करती हैं।

नोएडा को जाम से मिलेगी राहत! DND से सेक्टर 60 तक बनेगा 6 लाइन एलिवेटेड रोड, 700 करोड़ रुपए होंगे खर्च

आर्यावर्त संवाददाता

नोएडा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम से परेशान लोगों को जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है। शहर की सड़क व्यवस्था को बेहतर बनाने और वाहनों के दबाव को कम करने के लिए नोएडा अथॉरिटी एक महत्वाकांक्षी एलिवेटेड रोड परियोजना पर काम कर रहा है। इस परियोजना के तहत डीएनडी फ्लाईवे और रजनीगंधा अंडरपास से लेकर सेक्टर-60 तक छह लेन का एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। करीब 5।43 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के निर्माण पर लगभग 700 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

अफसरों के अनुसार, यह एलिवेटेड रोड नोएडा की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के साथ-साथ दिल्ली और नोएडा के बीच यात्रा को भी अधिक सुगम बनाएगा। वर्तमान में शहर के कई प्रमुख मार्गों पर कार्यालय समय के दौरान भारी ट्रैफिक दबाव रहता है, जिससे लोगों को लंबा जाम झेलना पड़ता है। नई परियोजना के पूरा होने के बाद इस समस्या में काफी हद तक कमी आने की उम्मीद है।

आईआईटी रुड़की बनाएगी DPR

परियोजना की तकनीकी रूपरेखा तैयार करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने की जिम्मेदारी आईआईटी रुड़की को सौंपी जाएगी। संस्थान रोड के डिजाइन, निर्माण की व्यवहार्यता, यातायात प्रबंधन और अन्य तकनीकी पहलुओं का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करेगा। डीपीआर तैयार होने के बाद टेंडर और निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नोएडा अथॉरिटी के अफसरों का मानना है कि यह परियोजना शहर के भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही है। आने वाले वर्षों में वाहनों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए यह एलिवेटेड रोड ट्रैफिक प्रबंधन में अहम भूमिका निभाएगा और नोएडा को एक बेहतर और आधुनिक परिवहन नेटवर्क उपलब्ध कराने में मदद करेगा।

जाम से मिलेगी राहत

प्रस्तावित एलिवेटेड रोड सेक्टर-3 से शुरू होकर सेक्टर-10, सेक्टर-12, सेक्टर-22 टी-पॉइंट और सेक्टर-57 होते हुए सेक्टर-60 तक पहुंचेगा। इसके बाद इसे एमपी-2 रोड से जोड़ने की भी योजना बनाई गई है। इस मार्ग के शुरू होने से नोएडा के आवासीय क्षेत्रों, औद्योगिक सेक्टरों और आईटी हब तक पहुंच आसान हो जाएगी। खासकर आईटी कंपनियों और औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों को रोजाना होने वाली ट्रैफिक परेशानी से राहत मिलेगी।

नोएडा अथॉरिटी का कहना है कि इस परियोजना का सबसे बड़ा फायदा यात्रा समय में कमी के रूप में देखने को मिलेगा। वर्तमान में इस रूट पर सफर करने में लगभग 30 मिनट तक का समय लग जाता है, लेकिन एलिवेटेड रोड बनने के बाद यही दूरी महज 10 मिनट में तय की जा सकेगी। इससे ईंधन की बचत होगी और लोगों का समय भी बचेगा।

प्रदेश के 36 जिलों में टीजीटी परीक्षा शुरू, करीब 50 फीसदी अभ्यर्थी उपस्थित

आर्यावर्त संवाददाता

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (यूपीईएसएससी) की ओर से आयोजित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) 2022 भर्ती परीक्षा बुधवार को प्रदेश के 36 केंद्रों पर शुरू हो गई है। यह परीक्षा तीन और चार जून को दो-दो पालियों में होगी। परीक्षा की निगरानी के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। एआई आधारित एकीकृत नियंत्रण कमांड कक्ष से इसकी निगरानी की जा रही है। साथ ही एसटीएफ की टीमें भी परीक्षा को सकुलश संपन्न कराने के लिए अलर्ट मोड में हैं। परीक्षा के लिए सुबह से ही केंद्रों पर अभ्यर्थियों की भीड़ जुट गई थी। सघन तलाशी के बाद उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। करीब चार वर्ष बाद हो रही टीजीटी 2022 परीक्षा में 8,68,531 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। प्रयागराज समेत प्रदेश के 36 जिलों में 614 केंद्रों पर सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे और 2:30 बजे से 4:30 बजे तक परीक्षा होगी। कंट्रोल रूम से अभ्यर्थियों की बायोमैट्रिक उपस्थिति एवं सत्यापन की प्रक्रिया का सीधा प्रसारण एवं रिकॉर्ड आयोग कार्यालय में उपलब्ध रहेगा। इससे परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की स्थिति में नियंत्रण कक्ष से त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की जा सकेगी।

बच्चे कम हो रहे पैदा...भारत में फर्टिलिटी रेट घटा, दक्षिण के राज्यों में हालत टाइट

भारत में प्रजनन दर को लेकर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे सामने आया है। ये 2023-24 की रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें एक महिला कितने बच्चे पैदा कर रही है इस पर जानकारी साझा की गई है। इसके मुताबिक भारत का फर्टिलिटी रेट 1.9 पहुंच गया है। जानें किन राज्यों में प्रजनन दर तेजी से घटी है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (एनएफएचएस) 2023-24 के मुताबिक भारत की प्रजनन दर (TFR) 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे पहुंच गई है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय महिलाओं में फर्टिलिटी रेट लगातार कम होता जा रहा है। टीएफआर का मतलब है कि एक महिला अपने फर्टिलिटी पीरियड (15 से 49 साल) की उम्र में ऑन एन एवरेज कितने बच्चों को जन्म देती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बिहार में प्रति महिला बच्चों की संख्या करीब 3 आंकी गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार में भी फर्टिलिटी रेट बेहतर है।

लेकिन दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु और केरल में ये आंकड़ा काफी गिरा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु में फर्टिलिटी रेट 1.6 देखा गया है। जानें इस रिपोर्ट के मुताबिक फर्टिलिटी रेट कैसा है और इसमें सुधार के लिए कौन-कौन से तरीकों को आजमा सकते हैं।

देश की औसत फर्टिलिटी रेट

यहां हम बात कर रहे हैं देश के जनसंख्या वृद्धि दर की। आज देश का औसत फर्टिलिटी रेट घटकर 2 से नीचे आ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में ये 1.9 पर आ गया है। बता दें कि भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) 2024 में 1।9 रही, जो रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से नीचे है। साल 1971 से 1981 के बीच टीएफआर 5.2 से 4।5 के बी था। 1991 से 2024 के बीच ये 3.6 से 1.9 पर आ गया। देखा जाए जाए तो साल 1971 से 2024 के आंकड़ों के मुताबिक ये 5.4 से घटकर 2.1 पर पहुंच गया है।

इस हिसाब से देखें तो भारत में एक महिला अपने फर्टिलिटी पीरियड में अब सिर्फ 2 बच्चे पैदा करती है। एक्सपर्ट बताते हैं कि किसी भी देश के राज्य या समाज को अपनी जनसंख्या को बनाए रखने के लिए फर्टिलिटी रेट कम से कम 2.1 चाहिए होता है। लेकिन पूरे देश का ये आंकड़ा 1.9 पर पहुंच गया है।

दक्षिण भारत के राज्यों हालत टाइट

तमिलनाडु में प्रजनन दर- दक्षिण भारत के 5 राज्यों की प्रजनन दर देखें तो यहां तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के शहरी इलाकों में एक महिला औसतन 1.6 बच्चों को जन्म देती है। जबिक इनके ग्रामीण इलाकों में आंध्र (2.0) और तमिलनाडु (1.8) का आंकड़ा सामने आया है। वैसे आंध्र प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में महिला की प्रजनन दर बेहतर आंकी गई है। तेलंगाना के शहरी इलाकों में यह दर मात्र 1.7 रह गई है। कर्नाटक और तेलंगाना के शहरी क्षेत्रों में प्रजनन दर 1.7 दर्ज की गई है। केरलम में शहरी दर 1.8 और ग्रामीण दर 1.9 दर्ज की गई है।

उत्तर भारत के राज्यों में प्रजनन दर

बिहार में प्रजनन दर देखी जाए तो यहां स्थिति बेहतर है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में एक महिला बच्चे पैदा करने का आंकड़ा 2.8 है, जबकि शहर में ये आंकड़ा 2.1 है। उत्तर प्रदेश 2.3 (ग्रामीण), 1.8 (शहरी), मध्य प्रदेश में 2.3 (ग्रामीण)- 1.7 (शहरी) और राजस्थान में 2.2 (ग्रामीण)- 1.7 (शहरी) आंकी गई है।

महिलाओं में क्यों घट रही प्रजनन दर

भारत में महिलाओं की प्रजनन दर घटने का एक बड़ा कारण देर से शादी करना है। शहरों में ये ज्यादा देखने को मिल रहा है।

करियर को प्राथमिकता देने कारण महिलाएं देरी से शादी शादी करती हैं और फर्टिलिटी घटने की दिक्कत हो जाती है। ज्यादातर महिलाएं नौकरी या बिजनेस में ज्यादा एक्टिव हैं।

छोटे परिवार की सोच के चलते भी महिलाओं और पुरुषों में फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है। लोग के बीच में हम दो, हमारे दो की सोच अधिक पॉपुलर हो रही है।

करियर को प्राथमिकता देने के अलावा लोगों में बढ़ता खर्च भी एक बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है। एजुकेशन, हेल्थ और लाइफस्टाइल से जुड़े खर्च या लागत बढ़ी है।

महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ी है। महिलाएं परिवार और मातृत्व से जुड़े फैसलों में अधिक भागीदारी कर रही हैं।

पंखे को साफ करें बिना स्टूल के

अक्सर पंखे की सफाई करने के लिए हमें स्टूल या सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि कभी-कभी खतरनाक भी होता है। लेकिन अगर आपको ऐसा तरीका मालूम हो जो सेफ भी हो और आपके पंखे को आसानी से साफ भी कर दे, तो कितना अच्छा होगा। आज हम आपको बताएंगे खास तरीके जिससे आप बिना स्टूल या सीढ़ी के अपने पंखे को साफ कर सकते हैं। यह तरीका न सिर्फ सेफ है, बल्कि इससे आपका समय भी बचेगा और पंखे अच्छे से साफ हो जाएगा। आइए जानते हैं यहां।।

फैन क्लीनर स्टिक का उपयोग करें

फैन क्लीनर स्टिक एक लंबे हैंडल वाला डस्टर होता है, जिसमें एक सिरे पर कपड़ा लगा होता है। यह बाजार में आसानी से उपलब्ध है और इसकी मदद से आप बिना ऊंचाई पर चढ़े पंखे के ब्लेड्स को अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं।

घरेलू क्लीनर का इस्तेमाल करें

एक बाउल में आधा कप तेल और नमक का मिश्रण बनाएं। इस मिश्रण को एक बाल्टी पानी में मिला लें और फैन क्लीनर स्टिक को इसमें भिगो दें। फिर इस स्टिक से पंखे के ब्लेड को साफ करें और बाद में साफ पानी से पोंछ दें। इससे आपका पंखा बिलकुल साफ हो जाएगा।

वैक्यूम क्लीनर का उपयोग

वैक्यूम क्लीनर भी पंखे की सफाई में मदद कर सकता है। वैक्यूम का हैंडल पकड़ें और इसे पंखे के नीचे लेकर जाएं। धूल और गंदगी वैक्यूम में चली जाएगी और आपका पंखा साफ हो जाएगा।

डस्टर का उपयोग करें

लंबे हैंडल वाला डस्टर आपके पंखे की पंखुड़ियों तक आसानी से पहुंच सकता है। डस्टर को पंखे की पंखुड़ियों पर फिराएं ताकि सारी धूल हट जाए।

माइक्रोफाइबर क्लॉथ का इस्तेमाल करें

डस्टिंग के बाद, माइक्रोफाइबर क्लॉथ को सफाई के स्प्रे से गीला करें और पंखुड़ियों को अच्छी तरह से पोंछें। यह कपड़ा धूल के कणों को अच्छी तरह से पकड़ लेगा और आपके पंखे को चमका देगा।

गर्मियों के दौरान क्यों अस्थिर हो जाता है शक्कर का स्तर? जानिए इसके 5 कारण

गर्मी का मौसम मधुमेह रोगियों के लिए चुनौतियों से भरा होता है। इस दौरान न केवल शक्कर के स्तर में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है, बल्कि शरीर में इंसुलिन का असर भी कम हो सकता है। इंसुलिन का असर कम होने से शरीर की कोशिकाएं शक्कर को सही तरीके से अवशोषित नहीं कर पाती हैं। आइए गर्मी के मौसम में शक्कर के स्तर में उतार-चढ़ाव आने के संभावित कारणों पर नजर डालते हैं।

भोजन का पाचन

गर्मियों के दौरान पाचन तंत्र की गति धीमी हो सकती है, जिससे भोजन का सही तरीके से पाचन नहीं हो पाता है। इससे शरीर में गैस, सूजन और अन्य पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसके कारण इंसुलिन का असर कम हो सकता है, क्योंकि शरीर की कोशिकाएं शक्कर को सही तरीके से अवशोषित नहीं कर पाती हैं। इससे शक्कर का स्तर अस्थिर हो सकता है और मधुमेह के लक्षण और भी गंभीर हो सकते हैं।

पानी की कमी

गर्मी के मौसम में पसीना अधिक आता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इससे इंसुलिन का असर कम हो जाता है और शक्कर का स्तर अस्थिर हो सकता है। इसके कारण मधुमेह रोगियों को थकान, कमजोरी और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, इस मौसम में अधिक से अधिक पानी पीएं और तरल पदार्थों का सेवन करें। साथ ही नमक युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें।

खाने की आदतें

गर्मी के मौसम में खाने की आदतें भी प्रभावित हो सकती हैं। कई लोग ठंडे पेय और तले हुए खाद्य पदार्थों का सेवन कर लेते हैं, जो सेहत के लिए सही नहीं होते हैं। इससे शरीर में सूजन बढ़ सकती है और इंसुलिन का असर कम हो सकता है। इसलिए, इस मौसम में पोषक तत्वों से भरपूर संतुलित आहार लें और जंक फूड से दूर रहें। इसके अलावा समय-समय पर अपने शक्कर के स्तर की जांच करवाते रहें।

व्यायाम की कमी

गर्मी से बचने के लिए कई लोग घर से बाहर नहीं निकलते और व्यायाम नहीं करते हैं, जिससे वजन बढ़ने लगता है। बढ़ता वजन इंसुलिन का असर कम कर सकता है। इसलिए, मधुमेह रोगियों को रोजाना कुछ मिनट व्यायाम जरूर करना चाहिए। इससे उनका वजन नियंत्रित रहेगा और मधुमेह के लक्षण भी कम हो जाएंगे। इसके अलावा व्यायाम से शरीर में शक्कर का सही तरीके से अवशोषण हो सकता है।

तनाव और अनिद्रा

तनाव और अनिद्रा भी शक्कर के स्तर को प्रभावित कर सकते हैं। तनाव से शरीर में एक हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जिससे इंसुलिन का असर कम हो सकता है। वहीं अनिद्रा से शरीर ठीक से काम नहीं कर पाता और शक्कर का स्तर अस्थिर हो सकता है। इसलिए, मधुमेह रोगियों को पर्याप्त नींद लेनी चाहिए और तनाव को कम करने के उपाय अपनाने चाहिए। इनकी मदद से आप शक्कर के स्तर को स्थिर रख सकते हैं।

क्या आपकी सनस्क्रीन सही से काम नहीं कर रही?

सनस्क्रीन का इस्तेमाल त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने के लिए किया जाता है। हालांकि, कभी-कभी सनस्क्रीन सही से काम नहीं करती, जिसका अंदाजा ज्यादातर लोगों को नहीं होता। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताते हैं, जिनसे पता चलता है कि आपकी सनस्क्रीन त्वचा की सुरक्षा नहीं कर रही। इन संकेतों को पहचानकर आप अपनी सनस्क्रीन को बेहतर बना सकते हैं और अपनी त्वचा को सूरज की किरणों से सुरक्षित रख सकते हैं।

त्वचा का रंग गहरा होना

अगर आपकी त्वचा धूप में रहने से सनस्क्रीन लगाने के बाद भी गहरी होती जा रही है तो समझ जाइए कि आपकी सनस्क्रीन सही से काम नहीं कर रही। इसका मतलब होता है कि आपकी त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से सुरक्षा नहीं मिल रही। ऐसे में हमेशा एक अच्छी गुणवत्ता वाली और ज्यादा सुरक्षा देने वाली सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें और इसे हर कुछ घंटों बाद दोबारा लगाएं।

जलन या लालिमा महसूस होना

अगर आपको अपनी त्वचा पर जलन या लालिमा महसूस होती है तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि आपकी सनस्क्रीन सही से काम नहीं कर रही। अगर आप धूप में रहने के बाद जलन या लालिमा महसूस करते हैं तो तुरंत छाया में जाएं और अपनी सनस्क्रीन को फिर से लगाएं। इस तरह आप अपनी त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचा सकते हैं और स्वस्थ रख सकते हैं।

त्वचा का रंग असमान होना

अगर आपकी त्वचा का रंग असमान लग रहा हो, जैसे कि धब्बे या कालापन दिखाई दे रहे हों तो इसका मतलब हो सकता है कि आपकी सनस्क्रीन सही से काम नहीं कर रही। ऐसी स्थिति में अपनी सनस्क्रीन को बदलें और यह सुनिश्चित करें कि वह आपकी त्वचा के प्रकार के अनुसार हो। अपनी सनस्क्रीन को सही तरीके से लगाएं, ताकि वह पूरी तरह से आपकी त्वचा को ढक सके और उसे सूरज की हानिकारक किरणों से बचा सके।

समय से पहले झुर्रियां आना

अगर आप समय से पहले झुर्रियों का अनुभव कर रहे हैं तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि आपकी सनस्क्रीन सही से काम नहीं कर रही। सूरज की हानिकारक किरणें हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे झुर्रियां जल्दी आती हैं। इसलिए, जरूरी है कि आप अपनी सनस्क्रीन को सही तरीके से लगाएं और नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करें, ताकि आपकी त्वचा युवा और स्वस्थ बनी रहे।

त्वचा का जल जाना

अगर आपको त्वचा का जलना महसूस होता है तो तुरंत अपनी सनस्क्रीन को बदलें। त्वचा पर जलन होने होने का मतलब है कि आपकी पुरानी सनस्क्रीन आपकी त्वचा को सही तरीके से सुरक्षा नहीं दे पा रही थी। हमेशा ज्यादा सुरक्षा देने वाली सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें और इसे हर कुछ घंटों बाद दोबारा लगाएं। इन संकेतों को पहचानकर आप अपनी त्वचा की देखभाल बेहतर तरीके से कर सकेंगे और सूरज की हानिकारक किरणों से सुरक्षित रख सकते हैं।

ग्लोबल ट्रेड वॉर की आहट! अमेरिका का 'सेक्शन 301' का हंटर, भारत समेत कई देशों पर नए टैरिफ का प्रस्ताव

यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) ने बुधवार को सेक्शन 301 की 60 फाइडिंग्स के नतीजे जारी किए। इसमें भारत के साथ-साथ 53 ऐसे देशों पर 12 .5 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया गया है, जो जबरदस्ती मजदूरी से बने सामान के इंपोर्ट पर रोक लगाने और उसे प्रभावी ढंग से लागू करने में नाकाम रही हैं। यह ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका के मुख्य वार्ताकार नई दिल्ली में अपने भारतीय समकक्षों के साथ एक बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने के लिए तीन-दिनों की बातचीत कर रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि नई दिल्ली बातचीत का मुख्य जोर सेक्शन 301 की फाइडिंग्स से राहत पाने और अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम टैरिफ हासिल करने पर रखेगा। अधिकारी ने कहा कि भारत इस डील को पक्का करने की कोशिश करेगा, बशर्ते उसे "शर्तें निष्पक्ष, न्यायसंगत और संतुलित" मिलें। उन्होंने यह भी कहा कि एक बार समझौते की मोटी-मोटी रूपरेखा तय हो जाने के बाद, US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर भारत का दौरा कर सकते हैं।

USTR की रिपोर्ट में क्या हैं तर्क?

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने जबरदस्ती मजदूरी वाले प्रावधान के तहत लगाए गए आरोपों से इनकार किया है और वाशिंगटन से इन जांचों को खत्म करने को कहा है। भारत का कहना है कि इन मुद्दों को एकतरफा उपायों के बजाय, चल रही व्यापार वार्ताओं के दायरे में ही सुलझाया जाना चाहिए।

USTR ने एक नोटिस में कहा कि जिन देशों ने जबरदस्ती मजदूरी से बने सामान के इंपोर्ट पर रोक लगाई है, या जिन्होंने 'पारस्परिक व्यापार समझौते' के जरिए ऐसी रोक लगाने और उसे लागू करने का वादा किया है, या फिर जिन अर्थव्यवस्थाओं ने एक ऐसी आंशिक व्यवस्था लागू की है जिससे ज़बरदस्ती मज़दूरी से बने कुछ खास सामानों का आयात रुक जाता है, उनके लिए US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने अतिरिक्त शुल्क की दर 10% रखने का प्रस्ताव दिया है।

दूसरे देशों के लिए USTR ने अतिरिक्त शुल्क की दर 12.5 फीसदी रखने का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही एक 'टेक्सटाइल मैकेनिज़्म' (कपड़ा व्यवस्था) का भी प्रस्ताव है, जिसके तहत कुछ खास इकोनॉमीज से अमेरिका में आने वाले कपड़ों और टेक्सटाइल के एक निश्चित आयतन पर सेक्शन 301 के तहत लगने वाला टैरिफ कम दर पर लगाया जाएगा। इस व्यापारिक संस्था ने इन जांचों के संबंध में जवाबी कार्रवाई के प्रस्ताव देने का भी निर्णय लिया है।

धारा 301 क्या है?

धारा 301, जो US ट्रेड एक्ट, 1074 का हिस्सा है, एक ट्रेड इंफोर्समेंट टूल है। यह USTR को विदेशी सरकारों के कार्यों, नीतियों और प्रथाओं की जांच करने का अधिकार देता है, और यह तय करता है कि क्या वे कार्य, पॉलिसीज और प्रथाएं अनुचित या भेदभावपूर्ण हैं, और क्या वे US ट्रेड पर बोझ डालती हैं या उसे प्रतिबंधित करती हैं। यदि सरकारी जांच में यह निष्कर्ष निकलता है कि अनुचित ट्रेड ट्रेडिशंस मौजूद हैं, तो यह धारा US को संबंधित देश पर अतिरिक्त टैरिफ या अन्य व्यापार-संबंधी उपाय लगाकर जवाब देने की अनुमति देती है। बुधवार को घोषित यह कदम US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उस प्रयास में एक बड़ा कदम है, जिसके तहत वे उन देश-वार टैरिफ को फिर से लागू करना चाहते हैं, जिन्हें उन्होंने अपने कार्यकाल के पहले वर्ष में लगाया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें असंवैधानिक घोषित कर दिया था।

नए US टैरिफ की समीक्षा

US सरकारी एजेंसी ने सूचित किया कि ये नए शुल्क तुरंत लागू नहीं होंगे। इन्हें लागू करने से पहले इन पर जनता की टिप्पणियां ली जाएंगी और इनकी समीक्षा की जाएगी। इसके परिणामस्वरूप, कोई भी शुल्क आधिकारिक रूप से लागू होने से पहले, उनमें बदलाव हो सकते हैं। नोटिस के अनुसार, लिखित टिप्पणियां 6 जुलाई तक जमा की जानी हैं, और धारा 301 पैनल द्वारा 7 जुलाई से सार्वजनिक सुनवाई शुरू करने की उम्मीद है।

ग्रीर ने एक बयान में कहा कि हमारे सबसे महत्वपूर्ण ट्रेडिंग पार्टनर्स द्वारा, जबरन लेबर से बने सामान के इंपोर्ट को रोकने में विफलता अस्वीकार्य है। इससे ऐसी स्थिति पैदा होती है, जहां अमेरिकी श्रमिकों को ग्लोबल लेवल पर एक असमान प्रतिस्पर्धा के माहौल में मुकाबला करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि हम अब इस असमानता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ग्रीर ने यह भी कहा कि इसका लक्ष्य व्यापार संबंधी जांचों की एक श्रृंखला को पूरा करना है, ताकि ट्रम्प, मौजूदा उपायों की समय सीमा समाप्त होने के बाद, जल्द से जल्द नए टैरिफ लागू कर सकें।

इस जांच में भारत को लेकर क्या?

USTR की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि नई दिल्ली, जबरन श्रम से बने सामान के आयात पर प्रतिबंध लगाने और उसे प्रभावी ढंग से लागू करने में विफल रही है। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि इस प्रतिबंध को लगाने और प्रभावी ढंग से लागू करने में विफलता "अनुचित" है, और यह US व्यापार पर बोझ डालती है या उसे प्रतिबंधित करती है। ग्रीर ने सभी ट्रेडिंग पार्टनर्स से आह्वान किया कि वे "यह सुनिश्चित करें कि व्यापार, वैश्विक स्तर पर जबरन श्रम को गलत तरीके से बढ़ावा न दे और न ही उसे और अधिक मजबूत करे।

सरकार बदलने जा रही होलसेल प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष, लॉन्च करेगी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स

नई दिल्ली, एजेंसी। सरकार थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स (डब्ल्यूपीआई) के आधार वर्ष को बदलकर 2022-23 करने जा रही है। इसके साथ ही उत्पादक मूल्य सूचकांक यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (पीपीआई) भी लॉन्च करने जा रही है, जिसे भारत की महंगाई मापने की प्रणाली को आधुनिक और अधिक सटीक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके अलावा, सरकार ने इस विषय पर मंगलवार को मीडिया को ब्रीफिंग के लिए आमंत्रित किया है, जिसे उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के प्रधान आर्थिक सलाहकार प्रवीण महतो संबोधित करेंगे।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा, 'हमने डब्ल्यूपीआई 2022-23 के आंकड़ों का उपयोग किया है, जो हमें आंतरिक रूप से उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि अप्रैल के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के आंकड़ों में कोई संशोधन न करना पड़े। हमें उम्मीद है कि ये आंकड़े अगले कुछ सप्ताह में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो जाएंगे।' उन्होंने बताया कि वर्तमान डब्ल्यूपीआई श्रृंखला का आधार वर्ष 2011-12 है, जबकि संशोधित श्रृंखला में इसे बदलकर 2022-23 कर दिया जाएगा। सौरभ गर्ग ने कहा कि नया सूचकांक शुरू होने के बाद भी डब्ल्यूपीआई से आउटपुट पीपीआई में बदलाव तुरंत नहीं किया जाएगा। सरकार पहले नई श्रृंखला की स्थिरता और विश्वसनीयता का अध्ययन करेगी, उसके बाद ही इसे व्यापक स्तर पर अपनाने का निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में डब्ल्यूपीआई और आउटपुट पीपीआई के बीच बहुत अधिक अंतर होने की संभावना नहीं है, क्योंकि डब्ल्यूपीआई की गणना के लिए पहले से ही ऐसी पद्धति अपनाई जाती है जो दोनों के बीच अंतर को सीमित रखती है। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब एक दिन पहले ही सांख्यिकी मंत्रालय ने 2022-23 आधार वर्ष के साथ संशोधित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) जारी किया था।

मंत्रालय ने बताया था कि मूल्य आधारित वस्तुओं की गणना के लिए नए आधार वर्ष वाले अद्यतन डब्ल्यूपीआई डिफ्लेटर का पहले ही इस्तेमाल किया जा चुका है। इस साल फरवरी में सरकार ने कहा था कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का आधार वर्ष 2022-23 किया जा रहा है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) का आधार वर्ष 2024 किया जा रहा है और आईआईपी का आधार वर्ष भी 2022-23 किया जा रहा है। इसके साथ ही भारत की सांख्यिकीय प्रणाली का व्यापक आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

सरकार के अनुसार, 'डब्ल्यूपीआई के आधार वर्ष में संशोधन का काम भी जारी है। जब तक नया डब्ल्यूपीआई उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक मौजूदा डब्ल्यूपीआई का उपयोग डिफ्लेटर के रूप में किया जाता रहेगा।' इसके अलावा, मंत्रालय निकट भविष्य में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (पीपीआई) को भी शामिल करने की योजना बना रहा है। पीपीआई उन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाले बदलाव को मापता है, जिन्हें उत्पादक खरीदते और बेचते हैं। इससे उत्पादन स्तर पर कीमतों के रुझान को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है और महंगाई के आकलन को अधिक सटीक बनाया जा सकता है।

व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर की नई तारीख आई, गोलीबारी के बाद टला था कार्यक्रम

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 जुलाई को होने वाले व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन (WHCA) डिनर में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम पहले 25 अप्रैल को होना था, लेकिन गोलीबारी की एक घटना के बाद इसे टाल दिया गया था। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उन्हें कार्यक्रम में आने और भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया है और उन्होंने यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया है।

25 अप्रैल को वॉशिंगटन में आयोजित हुए इस कार्यक्रम के दौरान एक हमलावर सिक्योरिटी पोस्ट तक पहुंच गया था। इसके बाद उसने शॉटगन से फायरिंग कर दी। उस समय ट्रंप भी कार्यक्रम में मौजूद थे। सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। घटना के बाद कार्यक्रम को

स्थगित कर दिया गया।

WHCA की अध्यक्ष और CBS News की वरिष्ठ व्हाइट हाउस संवाददाता वेइजिया जियांग ने एसोसिएशन के सदस्यों को पत्र लिखकर बताया कि कार्यक्रम को दोबारा आयोजित करने का फैसला आसान नहीं था। उन्होंने कहा कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी। साथ ही कार्यक्रम में प्रवेश के लिए नई प्रक्रिया भी लागू की जाएगी।

ट्रंप ने बताया कि यह कार्यक्रम वॉशिंगटन के वाल्डोर्फ एस्टोरिया होटल में आयोजित किया जाएगा। इस होटल को पहले ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने विकसित किया था। हालांकि कंपनी ने इसे 2022 में बेच दिया था। वेइजिया जियांग ने बताया कि एसोसिएशन ने अतिरिक्त धन जुटाया है ताकि जिन लोगों ने पहले टिकट खरीदे थे, उन्हें दोबारा पैसे न देने पड़ें।

100 साल पुराना है ये इवेंट

यह एनुअल इवेंट 100 साल से ज्यादा समय से आयोजित किया जा रहा है। इससे पत्रकारिता की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के लिए धन जुटाया जाता है। साथ ही यह अमेरिकी संविधान में दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र प्रेस के अधिकार का सम्मान भी करता है। 2011 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसी कार्यक्रम में ट्रंप पर मजाक किया था। उस समय ट्रंप एक कारोबारी और टीवी स्टार के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए थे।

दुनियाभर के दुर्लभ खनिज पर नजरें गड़ाए है अमेरिका! मार्को रूबियो बोले- हमारी कूटनीति का प्रमुख आधार

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि महत्वपूर्ण खनिज (क्रिटिकल मिनरल्स) अब अमेरिकी कूटनीति का एक प्रमुख आधार बन गए हैं। दुनिया भर में स्थित अमेरिकी दूतावास अब आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने और चीन पर निर्भरता कम करने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश विभाग और संबंधित कार्यक्रमों पर प्रतिनिधि सभा की विनियोग उपसमिति के सामने गवाही देते हुए रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने महत्वपूर्ण खनिजों को अपनी कूटनीतिक प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ प्रतिस्पर्धा अब केवल व्यापार और प्रौद्योगिकी तक सीमित नहीं है, बल्कि रणनीतिक संसाधनों तक भी फैल चुकी है। मार्को रूबियो ने कहा, 'दुनिया भर में हर अमेरिकी दूतावास में महत्वपूर्ण खनिज हमारी कूटनीति का एक प्रमुख हिस्सा हैं।' उन्होंने महत्वपूर्ण खनिजों को उन्नत विनिर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रक्षा प्रणालियों, सेमीकंडक्टर और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के भविष्य के लिए बेहद जरूरी बताया। उन्होंने बताया कि अमेरिका विभिन्न क्षेत्रों में अपने साझेदार देशों के साथ मिलकर वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाएं विकसित कर रहा है, ताकि खनन, शोधन और प्रसंस्करण में चीन के वर्चस्व से पैदा हुई कमजोरियों को कम किया जा सके। उन्होंने हाल की कूटनीतिक पहलों का भी जिक्र किया, जिनमें खनिज सुरक्षा और सहयोग पर केंद्रित अंतरराष्ट्रीय बैठकें शामिल हैं। रूबियो ने कहा, 'दुर्लभ खनिज को लेकर मंत्रिस्तरीय बैठक में तीन दर्जन से अधिक देशों ने भाग लिया था।' उनके अनुसार, अमेरिका की रणनीति केवल खनिज भंडारों तक पहुंच हासिल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि चीन के बाहर प्रसंस्करण और शोधन क्षमता बढ़ाने पर भी केंद्रित है। उन्होंने कहा कि इन सामग्रियों को इस्तेमाल योग्य उत्पाद में बदलने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई है। यह आर्थिक तथा राष्ट्रीय सुरक्षा योजना का अहम हिस्सा है। रूबियो ने बताया कि अमेरिकी राजनयिक अब दुनियाभर की सरकारों के साथ मिलकर आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों की पहचान कर रहे हैं और देशों को निवेश तथा विकास के वैकल्पिक स्रोतों से जोड़ने का काम कर रहे हैं।

अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास की तलाश करने वाले कई देशों के पास अक्सर चीन समर्थित परियोजनाओं के अलावा बहुत कम विकल्प होते हैं। रूबियो ने कहा, 'वहां केवल चीनी कंपनियां ही पहुंचती हैं।' उन्होंने इसे कई विकासशील देशों के सामने मौजूद एक बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि इसी कारण अमेरिका खनन, प्रसंस्करण, परिवहन और लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में अमेरिकी और सहयोगी देशों के विकल्पों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। इस प्रयास के तहत वित्तीय साधनों और समान सोच वाले देशों के साथ साझेदारी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि विशेष रूप से खनिज संसाधनों से समृद्ध क्षेत्रों में रणनीतिक परियोजनाओं को समर्थन दिया जा सके।

सऊदी अरब में पहली बार किसी हिंदू अफसर को बनाया गया राजदूत

सऊदी, एजेंसी। भारत सरकार ने सीनियर डिप्लोमैट विपुल को सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। वह सऊदी अरब में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त होने वाले वह पहले हिंदू IFS ऑफिसर हैं। उनसे पहले डॉ। सुहैल एजाज खान इस पद पर थे। डॉ। सुहैल एजाज खान ने 16 जनवरी 2023 को सऊदी अरब में भारत के राजदूत का कार्यभार संभाला था।

विदेश मंत्रालय (MEA) ने उनकी नियुक्ति की घोषणा करते हुए कहा कि विपुल जल्द ही सऊदी अरब में अपना नया पद संभालेंगे। फिलहाल वह कतर में भारत के राजदूत हैं और खाड़ी देशों में काम करने का लंबा अनुभव रखते हैं। विपुल 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी हैं। उन्होंने अपने करियर में कई देशों में भारत

का प्रतिनिधित्व किया है।

विपुल के राजनयिक अनुभव का फायदा मिलेगा

विपुल की नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब पश्चिम एशिया में लगातार तनाव बना हुआ है और सऊदी अरब की भूमिका पहले से ज्यादा अहम हो गई है। अपने लंबे राजनयिक करियर के दौरान विपुल ने मिस्र की राजधानी काहिरा, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, स्विट्जरलैंड के जिनेवा और संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में भारतीय मिशनों में काम किया है। इन जगहों पर उन्होंने राजनीतिक संबंध, व्यापार, विकास सहयोग, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, निरस्त्रीकरण और मीडिया मामलों जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जिम्मेदारी संभाली।

विदेश मंत्रालय में भी उनकी अहम भूमिका रही है। वह 2014 से 2017 तक विदेश मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी (संयुक्त सचिव) रहे। इस दौरान उन्होंने भारत की विदेश नीति से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों पर काम किया। इसके बाद 2017 से 2020 तक वह दुबई में भारत के कॉन्सुल जनरल (महावाणिज्य दूत) रहे। दुबई और खाड़ी क्षेत्र में उनके अनुभव को उनकी बड़ी ताकत माना जाता है।

भारत-सऊदी में सहयोग बढ़ा

भारत और सऊदी अरब के बीच पिछले कुछ वर्षों में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा और रणनीतिक सहयोग तेजी से बढ़ा है। सऊदी अरब में बड़ी संख्या में भारतीय भी रहते और काम करते हैं। ऐसे में विपुल की नियुक्ति को काफी अहम माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनके अनुभव का लाभ भारत और सऊदी अरब के रिश्तों को और मजबूत बनाने में मिलेगा।

बैक-टू-बैक 4 हमले...सीजफायर के बावजूद ईरान के केशम द्वीप पर अमेरिका क्यों बरसा रहा है बम?

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका ने होर्मुज नाकाबंदी के तहत ईरान के केशम द्वीप पर हमला किया है। सेंटकॉम का कहना है कि हेलफायर मिसाइल के जरिए उसने केशम द्वीप के पास एक तेल टैंकर को निशाने पर लिया है। इससे पहले 1 जून को भी अमेरिका ने केशम द्वीप पर हमला किया था। उस वक्त आत्मरक्षा की कार्रवाई के तहत अमेरिका ने केशम द्वीप पर हमला किया था। पूरे जंग में कम से कम 4 बार अमेरिका इस द्वीप पर हवाई हमला कर चुका है।

केशम द्वीप को होर्मुज का चेकपॉइंट्स माना जाता है। तेल और सुरक्षा दृष्टिकोण से ईरान का यह द्वीप काफी अहम है। यही वजह है कि द्वीप पर हमले के तुरंत बाद ईरान ने कुवैत और बहरीन स्थित अमेरिका के सैन्य बेस पर हमला किया।

अप्रैल की शुरुआत में ईरान और अमेरिका ने सीजफायर की घोषणा की

थी। इसके बाद दोनों के बीच परमाणु समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। मई के आखिर में अमेरिका ने ईरान के कुछ ठिकानों पर हमले की कोशिश की। अधिकांश हमले होर्मुज में किए जा रहे हैं।

वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक होर्मुज में ईरान की नाकाबंदी के खिलाफ अमेरिका ने ओमान की खाड़ी को ब्लॉक कर रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बावजूद ईरान के टैंकर तेल सप्लाई को निर्बाध रूप से जारी रखे हुए है। ईरान तमाम पाबंदियों के बीच रोजाना 1.5 मिलियन बैरल तेल बेच ले रहा है।

इस मिशन में केशम द्वीप की अहम भूमिका है। यह द्वीप होर्मुज के करीब है, जहां से टैंकरों को आसानी से ओमान की खाड़ी में एंटर कराया जाता है। यहां से टैंकर साइलेंट तरीके से चीन की ओर बढ़ जाते हैं।

केशम द्वीप की अहमियत क्यों?

1- इस द्वीप को ईरान का मिसाइल सिटी कहा जाता है। यहां पर जमीन के नीचे ईरान ने मिसाइलों को छुपा रखा है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के जवान इसी द्वीप से यूएई, कुवैत और अन्य खाड़ी देशों पर हमला करते हैं। यहां पर कई अंडरग्राउंड बंकर भी हैं।

2- ईरान के इस द्वीप से होर्मुज की पूरी मॉनिटरिंग की जाती है। द्वीप के जरिए होर्मुज के प्रवेश द्वार को इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के जवान कंट्रोल करते हैं। यह द्वीप पहाड़ों से घिरा है। यहां पर हमला या सैन्य ऑपरेशन दुश्मनों के लिए आसान नहीं है।

3- केशम तेल और गैस भंडार का एक अहम केंद्र है। केशम से 40 किलोमीटर दूर पर हेंगाम सेंटर से प्रतिदिन 1 लाख बैरल तेल प्रतिदिन निकाला जाता है। केशम में एक ऑयल टर्मिनल भी है, जहां पर तेलों को संसाधित किया जाता है।

सीमाओं की सुरक्षा होगी और मजबूत रोबोटिक तकनीक से बनेंगे आर्टिलरी शेल, बालू फोर्ज को मिला ऑर्डर

डिफेंस सेक्टर में नया 'टर्निंग पॉइंट'

कंपनी का मानना है कि यह ऑर्डर भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के विजन को और मजबूत करेगा। इस पूरी तरह से ऑटोमैटिक शेल प्रोडक्शन लाइन के साथ, कंपनी अब अपनी सहयोगी इकाई 'क्वांटम एनर्जेटिक्स' के जरिए एडवांस डिफेंस मैटेरियल्स के क्षेत्र में भी कदम बढ़ा रही है।

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय सेना के तोपखाने को और मजबूत करने के लिए देश में एक बड़ी शुरुआत होने जा रही है। अब भारतीय सेना के लिए बारूदी गोले इंसानों द्वारा नहीं, बल्कि एडवांस रोबोटिक तकनीक से बनाए जाएंगे। रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत 'बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड' को 30,000 स्वदेशी 152mm आर्टिलरी गोलों की सप्लाई का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस खास डील के तहत गोलों की सप्लाई इसी महीने यानी जून 2026 से शुरू होने जा रही है।

जानकारी के मुताबिक इन बारूदी गोलों का निर्माण कर्नाटक के बेलगाम में स्थित बालू फोर्ज की नई 'ग्रीनफील्ड' फैक्ट्री में किया जाएगा। इस प्लांट की सबसे बड़ी खासियत इसकी अत्याधुनिक तकनीक है। 100% स्वदेशी और ऑटोमैटिकः यह प्रोडक्शन लाइन पूरी तरह से स्वचालित है, यानी यहां इंसानों की सीधी भागीदारी नहीं होगी।

सटीकता और रफ्तारः रोबोटिक तकनीक से चलने के कारण इन बारूदी गोलों के निर्माण में गजब की सटीकता और जबरदस्त रफ्तार मिलेगी। इससे बिना किसी गलती के बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन संभव होगा।

बढ़ती मांग के लिए तैयारीः बड़े कैलिबर वाले गोला-बारूद की बढ़ती जरूरत को देखते हुए कंपनी इस रोबोटिक लाइन की क्षमता को और ज्यादा बढ़ाने पर काम कर रही है।

1 लाख से ज्यादा गोले बनाने का प्लान

शुरुआती तौर पर मिला यह 30,000 गोलों का ऑर्डर सिर्फ एक शुरुआत है। भविष्य में इस योजना के तहत 1 लाख से अधिक एडवांस गोले बनाने की तैयारी है। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं जैसे सभी संवेदनशील मोर्चों पर भारतीय सेना को हाई-कैपेसिटी वाले गोला-बारूद की लगातार और भरोसेमंद सप्लाई सुनिश्चित करना है।

कंपनी के पास इंटरनेशनल NATO सर्टिफिकेशन

बालू फोर्ज ने न केवल देश में बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी अपनी धाक जमाई है। कंपनी के पास NATO सर्टिफिकेशन है, जो यह साबित करता है कि इसके कड़े क्वालिटी कंट्रोल और मेटल की क्वालिटी अंतरराष्ट्रीय स्तर की है। इस सर्टिफिकेशन के कारण कंपनी नाटो देशों को भी रक्षा उपकरणों की सप्लाई करने की योग्यता रखती है।

पटना फायरिंग: खान सर ने सीएम सम्राट से लगाई सुरक्षा की गुहार, कोचिंग के बाहर भारी पुलिस बल तैनात

पटना, एजेंसी। अपने कोचिंग सेंटर के बाहर हुई गोलीबारी की घटना के बाद खान सर ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। पटना के मुसल्लापुर हाट के पास स्थित उनके कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रों की भारी भीड़ जमा हो गई। छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदशकारी छात्रों का कहना है कि खान सर को सुरक्षा मिले। कोचिंग संस्थान के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। खान सर ने कहा कि हमने अपने मुख्यमंत्री से सुरक्षा प्रदान करने की अपील की है। अब तक पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। हमारी सुरक्षा के लिए पूरी रात यहां 50-60 पुलिसकर्मी मौजूद थे। हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए मैं प्रशासन का धन्यवाद करता हूं। बता दें कि कल यानी मंगलवार की देर रात में उनके कोचिंग सेंटर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस घटना में उनका एक सुरक्षा गार्ड घायल हो गया।

हमले का CCTV सामने आया

खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है। वीडियो में लोग कोचिंग सेंटर पर पथराव करते दिख रहे हैं। सीसीटीवी में दिख रहा है कि कुछ लोग गार्ड से भी मारपीट कर रहे हैं। हमला करने वाले ये कौन लोग हैं, पुलिस इसकी जांच कर रही है।

8-10 राउंड फायरिंग का दावा

खान सर ने दावा करते हुए कहा कि हमलावरों ने करीब 8 से 10 राउंड फायरिंग की। इसके अलावा ऑफिस में भी पूरी तरह तोड़फोड़ की। हमारे सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट की। सुरक्षा गार्ड ने हमलावरों की पहचान कर ली है।

पुष्पा 2 द रूल का पहला गाना पुष्पा–पुष्पा रिलीज, मिका सिंह की आवाज और अल्लू अर्जुन के डांस ने ढाया कहर

साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पाः द रूल का पहला गाना पुष्पा-पुष्पा रिलीज हो गया है। इस गाने का फैंस काफी समय से इंतजार कर रहे थे। रॉकस्टार डीसीपी के लिखे गाने पुष्पा-पुष्पा को 6 भाषाओं में रिलीज किया गया है। पुष्पा-पुष्पा गाने के लिरिकल वीडियो ने पूरे इंटरनेट पर हलचल मचा दी है। फैंस अल्लू अर्जुन के स्टेप्स के कायल हो गए हैं और गाने पर भरपूर प्यार लुटा रहे हैं। वीडियो में पुष्पा ब्रांड की ताकत को दिखाया गया है।

गाने के जबरदस्त हुक स्टेप ने पुष्पाइज्म के क्रेज को बढ़ा दिया है, जो पुष्पाः द राइज के डेब्यू के बाद से पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया है।

पुष्पा 2 के पहले सिंगल पुष्पा-पुष्पा को 6 भाषाओं में रिलीज किया गया है। ये गाना तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़, मलयालम और बंगाली भाषाओं में रिलीज हुआ है। देवी श्री प्रसाद ने गाने के अलग-अलग वर्जन गाने के लिए नकाश अजीज, दीपक ब्लू, मीका सिंह, विजय प्रकाश, रंजीत गोविंद और तिमिर बिस्वास जैसे पॉपुलर सिंगर्स को शामिल किया है।

पुष्पा 2 का टीजर पहले ही रिलीज कर दिया गया था। सुकुमार के डायरेक्शन में बनी फिल्म पुष्पा 2 इसी साल 15 अगस्त को थिएटर्स में दस्तक देगी।

पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन के साथ एक बार फिर रश्मिका मंदाना लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आएंगी। इसके अलावा फहद फासिल भी फिल्म का हिस्सा होंगे। फिल्म से अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना का फर्स्ट लुक भी सामने आ चुका है। अब फैंस को बस फिल्म की रिलीज का इंतजार है।

अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म पुष्पा 2 साल 2021 की उनकी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म पुष्पाः द राइज का सीक्वल है। इस

फिल्म ने ना सिर्फ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर बल्कि वर्ल्डवाइड ताबड़तोड़ कलेक्शन किया था। फिल्म का डायलॉग- पुष्पा, मैं झुकेगा नहीं साला, काफी पॉपुलर हुआ था। इसके अलावा फिल्म के गाने श्रीवल्ली ने भी खूब वाहवाही बटोरी थी, जिसमें रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन की शानदार केमिस्ट्री दिखाई दी थी।पुष्पा 2 द रूल का पहला गाना पुष्पा-पुष्पा रिलीज, मिका सिंह की आवाज और अल्लू अर्जुन के डांस ने ढाया कहर

साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पाः द रूल का पहला गाना पुष्पा-पुष्पा रिलीज हो गया है। इस गाने का फैंस काफी समय से इंतजार कर रहे थे। रॉकस्टार डीसीपी के लिखे गाने पुष्पा-पुष्पा को 6 भाषाओं में रिलीज किया गया है।

पुष्पा-पुष्पा गाने के लिरिकल वीडियो ने पूरे इंटरनेट पर हलचल मचा दी है। फैंस अल्लू अर्जुन के स्टेप्स के कायल हो गए हैं और गाने पर भरपूर प्यार लुटा रहे हैं। वीडियो में पुष्पा ब्रांड की ताकत को दिखाया गया है।

गाने के जबरदस्त हुक स्टेप ने पुष्पाइज्म के क्रेज को बढ़ा दिया है, जो पुष्पाः द राइज के डेब्यू के बाद से पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया है।

पुष्पा 2 के पहले सिंगल पुष्पा-पुष्पा को 6 भाषाओं में रिलीज किया गया है। ये गाना तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़, मलयालम और बंगाली भाषाओं में रिलीज हुआ है।

देवी श्री प्रसाद ने गाने के अलग-अलग वर्जन गाने के लिए नकाश अजीज, दीपक ब्लू, मीका सिंह, विजय प्रकाश, रंजीत गोविंद और तिमिर बिस्वास जैसे पॉपुलर सिंगर्स को शामिल किया है।

पुष्पा 2 का टीजर पहले ही रिलीज कर दिया गया था। सुकुमार के डायरेक्शन में बनी फिल्म पुष्पा 2 इसी साल 15 अगस्त को थिएटर्स में दस्तक देगी।

पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन के साथ एक बार फिर रश्मिका मंदाना लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आएंगी। इसके अलावा फहद फासिल भी फिल्म का हिस्सा होंगे। फिल्म से अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना का फर्स्ट लुक भी सामने आ चुका है। अब फैंस को बस फिल्म की रिलीज का इंतजार है।

अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म पुष्पा 2 साल 2021 की उनकी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म पुष्पाः द राइज का सीक्वल है। इस फिल्म ने ना सिर्फ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर बल्कि वर्ल्डवाइड ताबड़तोड़ कलेक्शन किया था। फिल्म का डायलॉग- पुष्पा, मैं झुकेगा नहीं साला, काफी पॉपुलर हुआ था। इसके अलावा फिल्म के गाने श्रीवल्ली ने भी खूब वाहवाही बटोरी थी, जिसमें रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन की शानदार केमिस्ट्री दिखाई दी थी।

साउथ एक्ट्रेस टैग के चलते बॉलीवुड में काम मिलने में आ रही परेशानियां : सीरत कपूर

एक्ट्रेस सीरत कपूर का कहना है कि साउथ एक्ट्रेस के रूप में पहचाने जाने के चलते हिंदी सिनेमा में प्रोजेक्ट के ऑफर्स मिलने में परेशानियां हुई है।

31 वर्षीय एक्ट्रेस ने हिंदी सिनेमा में खुद को स्थापित करने में आ रही कठिनाइयों के बारे में बात की।

रणबीर कपूर स्टारर फिल्म रॉकस्टार में असिस्टेंट कोरियोग्राफर के रूप में सिनेमा में अपनी जर्नी शुरू करने वाली सीरत ने कहा, कई लोग मुझे साउथ एक्ट्रेस के रूप में जानते हैं और मुझे लगता है कि कभी-कभी यह बॉलीवुड में ऑफर्स मिलने के बीच रूकावटें पैदा करता है।

दर्शकों के लिए यह सोचना आसान है कि अगर आप साउथ इंडियन इंडस्ट्री में अच्छा कर रहे हैं तो आपको बॉलीवुड में आसानी से काम मिल सकता है। हालांकि, असल बात यह है कि बॉलीवुड में लीड रोल के लिए कोई भी प्रोजेक्ट पाने की प्रक्रिया बहुत चुनौतीपूर्ण है।

सीरत और भी बॉलीवुड फिल्में करने की इच्छुक हैं। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि मैं अपने लाइफटाइम में कम से कम एक बार बॉलीवुड एक्टर्स के साथ काम करूंगी। उन्होंने कहा कि तेलुगु सिनेमा से मेरा नाता हमेशा रहेगा।

उन्होंने कहा, टॉलीवुड ने मुझे वह सब कुछ दिया है जो आज मेरे पास है और मैं इसे पीछे नहीं छोड़ना चाहती। यहीं से मैंने शुरुआत की और यह हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा।

सीरत ने कई तेलुगु फिल्मों में काम किया है, जैसे रन राजा रन, टाइगर, राजू गरी गांधी 2, ओक्का क्षणम और मां विंता गाधा विनुमा आदि। 2022 में, उन्होंने तुषार कपूर के साथ मारीच के साथ हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत की।

बॉक्स ऑफिस पर 20वें दिन दैनिक कमाई में बड़े मियां छोटे मियां से आगे निकली मैदान

अजय देवगन की 'मैदान' और अक्षय कुमार की 'बड़े मियां छोटे मियां' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 20 दिन हो चुके है। दोनों ही फिल्मों का रिलीज से पहले काफी बज था हालांकि सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद ना 'मैदान' को और 'ना ही बड़े मियां छोटे मियां' को दर्शकों से कुछ खास रिस्पॉन्स मिला। फिलहाल ये फिल्में काफी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। चलिए यहां जानते हैं 'मैदान' और 'बड़े मियां छोटे मियां' ने रिलीज के 20वें दिन कितना कलेक्शन किया है?

एक्शन के तड़के से सजी फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' के ट्रेलर ने इस फिल्म को लेकर फैंस की काफी एक्साइटमेंट बढ़ा दी थी। वहीं फिल्म की स्टार कास्ट ने भी 'बड़े मियां छोटे मियां' का जमकर प्रमोशन किया था। जिसके बाद लग रहा था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दमदार कारोबार करेगी। रिलीज के बाद इसे क्रिटिक्स और दर्शकों से मिला-जुला रिव्यू मिला। हालांकि 'बड़े मियां छोटे मियां' ने ओपनिंग वीकेंड तक ठीक-ठाक कमाई की लेकिन फिर इसके कलेक्शन का ग्राफ गिरता चला गया और ये अभी तक बरकरार है।

फिल्म के कारोबार की बात करें तो 'बड़े मियां छोटे मियां' का पहले हफ्ते का कलेक्शन 49।9 करोड़ और दूसरे हफ्ते की कमाई 8।6 करोड़ रही। वहीं तीसरे हफ्ते के थर्ड मंडे फिल्म ने 40 लाख की कमाई। अब फिल्म की रिलीज के 20वें दिन यानी

तीसरे मंगलवार की कमाई के शुरुआती आंकड़े आ गए हैं।

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'बड़े मियां छोटे मियां' ने रिलीज के 20वें दिन 50 लाख की कमाई की है। इसी के साथ 'बड़े मियां छोटे मियां' का 20 दिनों का कुल कलेक्शन अब 61।60 करोड़ रुपये हो गया है।

अजय देवगन की स्पोर्ट्स ड्रामा देश के पॉपुलर फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम के जीवन पर आधारित है। उन्होंने फुटबॉल के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। इस फिल्म की इंस्पायरिंग कहानी और अजय देवगन की एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है। हालांकि 'मैदान' टिकट काउंटर पर उम्मीद के मुताबिक कारोबार नहीं कर पाई है।

हालांकि तीसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई में थोड़ी तेजी देखी जा रही है। 'मैदान' के कलेक्शन कि बात करें तो इस फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते में 28।35 करोड़ और दूसरे हफ्ते में 9।95 करोड़ की कमाई की थी। वहीं रिलीज के तीसरे हफ्ते के तीसरे मंडे 'मैदान' ने 50 लाख की कमाई की और अब इस फिल्म की रिलीज के 20वें दिन यानी तीसरे मंगलवार की कमाई के शुरुआती आंकड़े आ गए हैं।

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'मैदान' ने रिलीज के 20वें दिन यानी तीसरे मंगलवार को 70 लाख की कमाई की है। इसी के साथ 'मैदान' का 20 दिनों का कुल कलेक्शन अब 43।95 करोड़ रुपये हो गया है।

'मैदान' की कमाई की रफ्तार में तीसरे हफ्ते में थोड़ी तेजी देखी जा रही है। 100 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म अब 50 करोड़ का आंकड़ा छूने की और बढ़ रही है। फिल्म की रफ्तार को देखते हुए लग रहा है कि ये इस आंकड़े को पार कर लेगी। हालांकि 'बड़े मियां छोटे मियां' का टिकट खिड़की पर बुरा हाल है। ये फिल्म मैदान के आगे अब फीकी पड़ रही है। 300 करोड़ से ज्यादा के बजट में बनी ये फिल्म 20 दिन बाद भी 100 करोड से कोसो दूर है।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित ।
शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website : aryavartkranti.com
*सम्पादकः प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com